चिंतन

'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' पर सुप्रीम फैसला ऐतिहासिक

चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। शीर्ष अदालत ने फैसला दिया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी (अश्लील सामग्री) देखना, डाउनलोड करना पॉक्सो और आईटी कानून के तहत अपराध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को सुझाव भी दिया है कि संसद को कानून में संशोधन कर 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द को बदलकर 'बच्चों के साथ यौन शोषण और अश्लील सामग्री' करने पर विचार करना चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना अपराध नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाने में गंभीर गलती की है। 11 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई के एस हरीश (28) नामक एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद कर दी थी। हरीश पर अपने मोबाइल फोन पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री डाउनलोड करने का आरोप लगाया गया था। शीर्ष अदालत में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। खास बात है कि फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कई दिशा-निर्देश भी दिए हैं। किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कंटेंट को देखना, डिस्ट्रीब्यूट करना या प्रदर्शित करना, किसी भी डिवाइस या अन्य तरीके से ऐसे कंटेंट के रियल या फिजिकल पजेशन या स्टोरेज के साथ या उसके बिना, पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध है। किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है यदि यह साबित हो जाता है कि उसने मामला शुरू होने या एफआईआर दर्ज होने से पहले कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट 'स्टोर्ड' या 'अपने पास' रखी थी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कानूनी और नैतिक परिणामों के बारे में जानकारी शामिल करते हुए व्यापक यौन शिक्षा प्रोग्राम को लागू करने से संभावित अपराधियों को रोकने में मदद मिल सकती है। यौन शिक्षा को पश्चिमी अवधारणा मानकर इसे शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाना सही नहीं है। शिक्षकों, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और कानून लागू करने वाले अधिकारियों को समस्याग्रस्त यौन व्यवहार के संकेतों की पहचान करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। दरअसल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वैश्विक समस्या है, अश्लील कंटेंट का बाल मन पर गहरा व विकृत प्रभाव पड़ता है। स्मार्टफोन के चलन में आने के बाद से मोबाइल पर अश्लील कंटेंट की भरमार है, जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़ने का खतरा है। बाल यौन शोषण का मामला भी बढ़ा है। अब संसद को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम में संशोधन को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि ऐसे अपराधों की वास्तविकता को और अधिक सटीक रूप से दर्शाया जा सके। तब तक सरकार पॉक्सो अधिनियम में सुझाए गए संशोधन के लिए अध्यादेश ला सकती है। बाल यौन शोषण सामग्री नाबालिगों की गरिमा को बहुत अधिक ठेस पहुंचाती है और यह उन्हें यौन संतुष्टि की वस्तु बना देती है, उनकी मानवता का हरण कर लेती है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। बच्चों को ऐसे माहौल में पलने-बढ़ने का अधिकार है, जहां उनकी गरिमा का सम्मान हो और उन्हें नुकसान से बचाया जाए। बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसईएएम) का उत्पादन, वितरण और उपभोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना स्पष्ट कानूनी और नैतिक अनिवार्यता है। यौन शोषण का कोई भी कृत्य स्वाभाविक रूप से बच्चे पर स्थायी शारीरिक और भावनात्मक आघात पहुंचाता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पोक्सो) एक्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सख्त सजा का प्रावधान है।

दिल्ली

डॉ. रमेश ठाकुर

चुनौतियों संग 'आतिशी' पारी शुरू

मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं...के साथ ही आतिशी दिल्ली की 8वीं और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गईं। पार्टी ने बहुत सोच समझकर उन्हें ये पद सौंपा है। महिला हैं, विश्वास पात्र हैं और पार्टी के प्रति पूर्ण वफादार भी हैं, इसलिए, वरना अरविंद केजरीवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जैसा जोखिम जानबूझकर नहीं उठाते। उन दोनों ने भी कभी अपनी जगह जीतनराम मांझी और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी, जिन्होंने कुछ महीनों में ही आंखें दिखानी शुरू कर दी थीं। खैर, केजरीवाल भी इस कड़ी में शामिल होते, उसके लिए उन्होंने गंभीरता से होमवर्क करके ही अपनी सीट पर आतिशी को बैठाने का निर्णय लिया। दिल्ली में अगले चार-पांच महीनों के भीतर ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब से कुछ समय बाद ही आचार संहिता लग जानी है। पार्टी कार्यकर्ता आतिशी की ताजपोशी को बेशक 'आतिशी पारी' कह रहे हों, पर चुनौतियों की भी कोई कमी नहीं है? सभी भली-भांति जानते हैं कि नई मुख्यमंत्री के लिए करने को कुछ ज्यादा नहीं है। सिर्फ नाम भर की मुख्यमंत्री रहेंगी। ये भी सच है कि कुर्सी पर बेशक आतिशी बैठें, लेकिन

चलाएंगे केजरीवाल ही? सरकार संचालन का रिमोट केजरीवाल के पास ही सदैव होगा। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल अभी कोर्ट-कचहरी और कानूनी पचड़े में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आतिशी को दिल्ली की कमान सौंपने के पीछे एक वजह ये भी है कि वो महिला हैं, इसलिए विपक्ष खासकर भाजपा खुलकर हमलावर नहीं होगी। पार्टी नेताओं की माने तो आतिशी को चुनाव तक के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच वो गड़बड़ाई पार्टी की स्थिति को कितना संभाल पाती हैं, ये उनके सामने कड़ी परीक्षा जैसी रहेगी। फिलहाल राज निवास में आयोजित एक समारोह में शनिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने भारत की 17वीं महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी हासिल कर लिया। समारोह में मौजूद रहे विपक्षी नेता बिजेंद्र गुप्ता, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बधाइयां दी। दिल्ली के कालकाजी से विधायक आतिशी ने शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। आतिशी आम आदमी पार्टी के कोटे से चौथी मुख्यमंत्री बनी हैं, उनसे पूर्व 3 मर्तबा पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। आतिशी की जगह अगर कोई पुरुष नेता मुख्यमंत्री बनता, तो भाजपा हमलावर होती, इसलिए केजरीवाल ने महिला को सीएम की कुर्सी सौंपकर बड़ा सियासी दांव खेला है। मुख्यमंत्री आतिशी के समक्ष चुनौतियां बेशक हजार हों, लेकिन पार्टी उनके पीछे खड़ी है। पार्टी उन्हें चुनाव तक धुंआधार पारी खेलने का मौका देगी, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी की वापसी भी करवानी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगले वर्ष होने वाले चुनाव तक मुख्यमंत्री आतिशी पार्टी की वापसी करवा पाएंगी या नहीं? दिल्ली के सरकारी कामकाज काफी हद तक रुके हुए हैं। उन्हें दोबारा से संचालित करना होगा। पार्टी के कई नेता नाराज होकर दूसरे दलों में चले गए हैं और कोई न जाए, उन्हें रोकना होगा। रूठे नेताओं को मनाना होगा। एमसीडी जोन चुनाव में पार्टी भाजपा से पिछड़ चुकी है, दोबारा से पटरी पर लाना होगा। ऐसे कई मुद्दे नई मुख्यमंत्री के सामने मुंह खोले खड़े हैं। उन सभी पर उन्हें पार पाना होगा। कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं। अगले सप्ताह विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य महका भी चरमरा गया है, जबकि ये ऐसे महकमे हैं जिनके बूते उनकी पार्टी प्रचार करती है। शिक्षा में क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया भी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। दिल्ली में पूर्व के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल पर अगर नजर डालें, तो कइयों का बहुत अच्छा इतिहास और शानदार कार्यकाल रहा। पहले मुख्यमंत्री थे ब्रह्म प्रकाश, जो 17 मार्च 1952 से लेकर 12 फरवरी 1955 तक दिल्ली के मुखिया रहे। वहीं, पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी जिनका कार्यकाल कम अवधि का था, वह 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक ही मुख्यमंत्री रहीं। दूसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित ने लंबा कार्यकाल बिताया। अब आतिशी की पारी का आगाज हुआ है। दिल्लीवासियों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, देखते वह कितना खरा उतर पाती हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मिलावटी घी ने लगाया सियासत में तड़का

विचार

डॉ. संजय शुक्ला

आंध्र प्रदेश के तिरूमला - तिरूपति के बालाजी मंदिर के प्रसादम के तौर पर मिलने वाले लड्डू में प्रयुक्त घी में पशुओं की चर्बी के मिलावट पर उठे राजनीतिक बवाल ने देश का सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि गुजरात स्थित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 'एनडीडीबी' के प्रयोगशाला में प्रसादम 'लड्डू' बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी का बीते 9 जुलाई को सैंपल लिया था और 16 जुलाई को लैब ने अपना रिपोर्ट जारी किया जिसमें पशु चर्बी और मछली के तेल के मिलावट की पुष्टि की। हालांकि यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट जारी करने के बाद ही उपलब्ध था लेकिन आंध्रप्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के इस रिपोर्ट को मीडिया में लाने और इस मिलावट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआरसी नेता जगनमोहन रेड्डी को कठघरे में खड़ा करने के बाद इस मिलावटी घी ने सियासत की आग को भड़का दिया है। सोशल मीडिया में भी यह मसला खूब उछल रहा है जिसमें यूजर्स लगातार तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

गौरतलब है कि तिरूमला - तिरूपति के बालाजी मंदिर के प्रति केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की अपार आस्था है जहां बीते 300 वर्षों से प्रसादम के तौर पर रोज साढ़े तीन लाख लड्डू बनते हैं। लड्डू बनाने के लिए बीते पचास वर्षों से कर्नाटक को-ऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन 'केएमएफ' द्वारा रियायती दर पर घी उपलब्ध कराया जा रहा था। केएमएफ द्वारा रियायती कीमत पर घी उपलब्ध कराने में असमर्थता जताने पर पूर्ववर्ती जगनमोहन रेड्डी सरकार ने बाजार में पांच निजी फर्मों को घी आपूर्ति का ठेका दे दिया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है कि मिलावटी घी की आपूर्ति जगन रेड्डी के वाईएसआरसी से जुड़े लोगों के फर्मों से हुई है। दूसरी ओर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने आरोपों को खारिज करते हुए नायडू पर राजनीतिक लाभ के लिए घृणित राजनीति करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने जहां इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी नड्डा ने आंध्र प्रदेश सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट तलब करने का है। दूसरी ओर पूर्ववर्ती सरकार ने जिन फर्मों से जिस कीमत पर घी खरीदने का अनुबंध किया है उससे घी में मिलावट के रिपोर्ट को कतई खारिज नहीं किया जा सकता। खबरों के मुताबिक संबंधित फर्मों ने 319 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से घी आपूर्ति करने पर रजामंदी दी गई थी लेकिन दूध व्यवसाय से जुड़े विशेषज्ञों के लिहाज से इस दर पर घी मुहैया कराना संभव ही नहीं है। अलबत्ता प्रसादम 'लड्डू' में पशुओं की चर्बी और मछली का तेल मिलने की खबरों ने तिरुपति बालाजी के करोड़ों भक्तों के आस्था पर करारा चोट पहुंचाया है साथ ही इससे आंध्र प्रदेश सरकार और तिरूमला - तिरूपति देवस्थानम ट्रस्ट की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है।

अलबत्ता तिरूपति बालाजी के प्रसादम लड्डू के लिए प्रयुक्त घी में मिलावट सिर्फ राजनीतिक विवाद या धार्मिक आस्था का ही मुद्दा नहीं है बल्कि यह आम आदमी के सेहत से भी जुड़ा मसला है। भारत में दैनिक उपयोग के खाद्य पदार्थों और अन्य जिंसों में मिलावट एक आम समस्या बन चुकी है जिसका शिकार उपभोक्ता हो रहे हैं। सामान्यतया रोजमर्रा के उपयोग में काम आने वाले दूध, घी, खोया वनि मावा, छाछ, पनीर, वनस्पति घी, खाद्य तेल, शहद, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, मसाले, चांवल, दाल, बेसन, आटा, चाय - कॉफी, आईसक्रीम, कोल्डड्रिंक, बोतलबंद पानी, तंबाकू और गुटका सहित मांसाहारी खाद्य पदार्थों में मिलावट आम है। आश्चर्यजनक यह कि मिलावट सिर्फ खाद्य पदार्थों में ही नहीं हो रहा है बल्कि दवाओं में भी हो रहा मिलावट जानलेवा साबित हो रहा है। विचारणीय है कि सरकार के तमाम कानूनों और एजेंसियों के बावजूद मिलावटखोरों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। भारत एक उत्सव प्रधान देश है जहां हर धर्म और जाति के लोगों द्वारा विभिन्न त्योहार और पर्व मनाया जाता है इस दौरान सबसे ज्यादा खपत खाद्य पदार्थों की होती है। त्योहारी सीजन में दूध से बने पदार्थों जैसे खोया या मावा, मिठाई, घी और पनीर में मिलावट की खबरें आम हो चुकी है। त्योहारों का सीधा संबंध मिठाई और नमकीन से है लेकिन त्योहारी सीजन में बाजार में बिकने वाले दूध से बनी मिठाईयों और खोया में मिलावट की सर्वाधिक आशंका होती है।

सरकार और प्रशासन के तमाम कोशिशों के बावजूद बीते कुछ सालों में मिलावटी, दूषित, गुणवत्ताहीन और नकली ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस त्योहारों के दौरान बाजार में बिकने वाले खाने-पीने के 60 से 65 फीसदी वस्तुओं में मिलावट होती है जो सेहत को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। विभिन्न त्योहारों के दौरान मांग की तुलना में खोया के कम उत्पादन का फायदा नकली और मिलावटी खोया बेचने वाले उठाते हैं जो अपने अनैतिक कमाई के लालच में लोगों की जान सांसत में डालने से भी नहीं हिचकते। नकली खोया बनाने के दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा और मेलामाइन पावडर मिलाया जाता है। मिलावटी खोया में स्टार्च, आयोडीन,आलू, सिंघाड़े का आटा, मैदा, टेल्कम पावडर और दूध पावडर इत्यादि मिलाया जाता है। नकली और मिलावटी खोया से उल्टी-दस्त, अपचन, पाचनतंत्र से संबंधित रोग, लिवर और किडनी के रोग होते हैं। इसके अलावा मिठाईयों में एल्यूमिनियम का वर्क, प्रतिबंधित रंगों और एसेंस तथा सैक्रिन के प्रयोग से सेहत संबंधी दिक्कतें आती है।

देसी घी जिसे आमतौर पर शक्तिवर्धक माना जाता है में वनस्पति तेल और घी, नारियल तेल, पिघला हुआ मक्खन,आलू और शकरकंद, हाइड्रोजनेटेड ऑयल के साथ पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है। इस मिलावट के चलते घी की गुणवत्ता, शुद्धता, स्वाद और पोषण में काफी गिरावट आती है। इसके अलावा चांवल में अब प्लास्टिक, दालों में खेसरी दाल, कंकड़ और रंग, आटे में चाक पावडर, मैदा और अन्य आटे, सब्जियों या फलों को पकाने या रंगीन व चमकदार दिखाने के लिए कार्बाइड, हानिकारक रसायन और रंग, मोम आदि का मिलावट या प्रयोग किया जा रहा है। मांस और अंडे में मीट ग्लू, चूहे या अन्य पशुओं के मांस, जिलेटिन, कार्मिन, नाइट्रेट, मोम, जिप्सम पावडर, कैल्शियम कार्बोनेट और कृत्रिम रंगों का मिलावट किया जा रहा है। इस मिलावट से व्यक्ति में कैंसर से लेकर उच्च रक्तचाप, हृदय, किडनी, लिवर सहित पाचन तंत्र से जुड़े और अनेक मानसिक रोग हो सकते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की वजह से लगभग 200 प्रकार की बीमारियां होती है। एक शोध के अनुसार भारत में 52 फीसदी बीमारी मिलावटी खान-पान की वजह से हो रही है।

बहरहाल भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाना सरकार और समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सामग्री को मिलावट को रोकथाम तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के लिए साल 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 'पीएफए एक्ट 1954' लागू है। इसके अलावा देश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 लागू है जिसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। अनेक राज्यों में मिलावट करने वालों को 10 लाख जुर्माना, गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तारी और आजीवन कारावास का भी कानून है। खाद्य पदार्थों में हानिकारक मिलावट का मामला कई बार संसद में उठ चुका है लेकिन नतीजा सिफर ही रहा हैतमाम कानूनों के बावजूद खाद्य नमूनों के जांच रिपोर्ट में देरी और अदालती फैसलों में विलंब तथा आरोप सिद्ध करने में नाकामी के चलते मिलावटखोरों के पौ बारह हैं।

आहम तथ्य यह भी कि खाद्य और औषधियों में मिलावट रोकने के लिए जिम्मेदार सरकारी विभाग की जवाबदेही है कि वह आम उपभोक्ता सामग्रियों का नियमित सैंपल ले और इसका लैबोरेटरी में परीक्षण कराएं लेकिन यह अमला केवल त्योहारों के दौरान ही सक्रिय होता है।आश्चर्यजनक तौर पर इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट तब आती है जब सारा त्योहर निबट चुका होता है।अधिकांश मामलों में थोड़ा- बहुत जुर्माना लगाकर कानून पालन का रस्म अदायगी कर लिया जाता है। दरअसल देश में मिलावटखोरों के खिलाफ शिकंजा कसने में नाकामी के पीछे अहम कारण खाद्य, स्वास्थ्य और औषधि प्रशासन विभाग में शीर्ष स्तर से लेकर नीचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी है। इसके अलावा देश में आवश्यकता के लिहाज से खाद्य नमूनों के जांच हेतु अति उन्नत टेस्टिंग लैबोरेटरी की कमी होना भी है। हालांकि फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 'एफएसएसएआई' ने देश भर में मोबाइल टेस्टिंग लैब उपलब्ध कराने की घोषणा की है लेकिन इस घोषणा का धरातलीय क्रियान्वयन में अभी काफी रोड़े हैं।अलबत्ता सरकार और प्रशासन को खाद्य पदार्थों तथा दवाओं में मिलावट रोकने की दिशा में ठोस प्रबंध करने की जरूरत है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण संगठनों से भी अपेक्षा है कि वह आम लोगों को मिलावट के खिलाफ जागरूक करें। बहरहाल हालिया सियासी विवाद के मद्देनजर राजनीतिक दलों और राजनेताओं से भी अपेक्षा है कि वह इसे सिर्फ विवाद का मुद्दा न बनाएं बल्कि समाधान की दिशा में भी दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शित करें आखिरकार यह जनस्वास्थ्य से जुड़ा मसला है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

गलतियों को खुले मन से स्वीकार करें

संकलित

दर्शन

कार्य संपन्न होने की प्रक्रिया में कदाचित त्रुटियां रह सकती हैं, भले ही कार्य निष्ठा से किया जाए। अगर कोई आपके किए-कराए में चूक निकाले, उस पर टिप्पणी करे तो नाराज होने के बजाय उसे खुलेमन से स्वीकार करें। वैसे आप गलतियां करने से तभी बच पाएंगे, जब कुछ नहीं करेंगे। अपने अवगुण या खोट को स्वीकार करना श्रेष्ठ मानवीय गुण है। औसत सोच का व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ होता है। अवांछनीय या अनुचित कार्य की अनदेखी का अर्थ है संशोधन के द्वार बंद कर देना। सर्वगुणसंपन्न व्यक्ति तो साक्षात देवता है। भूल-चूक की स्वीकारोक्ति प्रगति की राह में पहला चरण है। इस प्रक्रिया में आप अनेक व्यक्तियों का विश्वास जीतते हैं। जिस सत्य का सामना करने के लिए तैयार नहीं, उसे बदलेंगे कैसे? जिसे अपनी अपूर्णताओं का आभास नहीं वह मूर्ख नहीं, बल्कि दयनीय है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने अवगुणों को दूर नहीं कर सकेगा। जिस सीमा तक हम अपनी अपूर्णताओं और अवांछनीय व्यवहार के प्रति सजग रहेंगे और समाधान की ओर अग्रसर रहेंगे, उसी अनुपात में हम नैतिक रूप से समृद्ध होंगे। व्यावहारिक जीवन में संयमी, संयत व्यक्ति से भी भूल-चूक हो जाती है। उन्नत सोच का व्यक्ति अपनी भूल को तुरंत स्वीकार कर लेगा। मध्यम सोच वाले को गलती का अहसास तो होगा, वह मन में कुढ़ेगा भी, किंतु लज्जित होने की आशंका से वह गलती को खुलेआम नहीं मानेगा। अपनी छवि के प्रति अत्यंत चौकस अधिसंख्य व्यक्ति अपने गलत कार्य या कथन की वैसी संरक्षा करेंगे जैसे सहूम या शील दांव पर हो।

अच्छी बातें जीवन में उतारने पर ही लाभ मिलेगा

संकलित

प्रेरणा

द्वापर युग में द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह ने कौरव और पांडव राजकुमारों का गुरु बना दिया था। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को एक पाठ दिया और कहा कि कल इस पाठ को आत्मसात करके आना है। आत्मसात शब्द का अर्थ है जीवन में, अपने आचरण में उतारना। अगले दिन सभी राजकुमार गुरु के आश्रम में पहुंच गए। पढ़ाई शुरू हुई तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि कौन-कौन कल का पाठ याद करके आया है? युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी सभी राजकुमारों ने कह दिया कि हमने ये पाठ याद कर लिया है। गुरु ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने पाठ याद क्यों नहीं किया है? युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने अभी तक ये पाठ आत्मसात नहीं किया है। ये बात सुनकर द्रोणाचार्य हैरान थे। कुछ देर सोचकर गुरु ने कहा कि ठीक है कल याद कर करके आना। इसके बाद दस दिन बीत गए, लेकिन युधिष्ठिर को वो पाठ अब तक याद नहीं हुआ था। जबकि अन्य राजकुमार युधिष्ठिर से 10 पाठ आगे पहुंच गए थे। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि आखिर बात क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, जैसे मेरे भाइयों ने ये पाठ याद किया है, वैसे तो मुझे याद है, लेकिन आपने कहा था कि इस पाठ को आत्मसात करना है। आपने सत्य को जीवन में उतारने का पाठ दिया था और मैं सत्य को जीवन में उतार नहीं पा रहा हूं। जब तक मैं इसे आत्मसात नहीं कर लूंगा, जब तक मैं सत्य को जीवन में नहीं उतार लूंगा, तब तक मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा।

अंतर्मन

आज की पाती

भारत सरकार पुरुष दिवस मनाने की घोषणा करे

अपने देश में बहुत से दिवस मनाने का रिवाज है। वर्षों से बाल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद कई और दिन मनाने शुरू कर दिए। देश में जिस प्रकार कामुक रोगी मानसिकता वाले लोग लड़कियों का यौन शोषण और यौन उत्पीड़न करते हैं, उसके लिए सरकार कितने भी कानून बना ले, कितना भी दंड बढ़ा ले, पर मेरा यह विश्वास है कि केवल कानून से सामाजिक क्रांति, समाज सुधार नहीं हो सकता। इसके लिए सभी धर्मों के सभी धर्म गुरुओं को जागृति पैदा करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही भारत सरकार कम से कम एक वर्ष के लिए हर महीने पुरुष दिवस मनाना शुरू करे। उस दिन महिलाएं अपने परिवारों के सभी पुरुष सदस्यों से यह शपथ ले कि वे कभी भी किसी भी महिला पर कुदृष्टि नहीं रखेंगे व उसके सम्मान की रक्षा में भागीदार बनेंगे। - शंकर बघेल, राजनांदगांव

ट्रेंड

बेहतर स्वास्थ्य की सौगात

आयुष्मान भारत योजना के अलावा मुफ्त इलाज गरीबों और वंचित वर्गों के लिए वरदान साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के माध्यम से हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य की सौगात दी है।

-धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री

भविष्य का दरवाजा खोला

भविष्य के लिए सघि, वैक्सिन डिस्टिल फॉर्मेशन और मशिन की पीढ़ियों पर पीछा को आगामने से नई संभावनाओं और अवसरों के रास्ते खुलते हैं। हमने सारा भविष्य का दरवाजा खोल दिया है।

-एंटोनियो गुतारेस, यूएन महासचिव

खिलाड़ियों ने इतिहास रचा

हॉकेज ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। ओपन सेशन में पुरुष टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता। महिला वर्ग में भी भारतीय टीम ने पहली बार गोल्ड जीता है। सभी खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई। आप सब पर पूरे देश को गर्व है। जय हिंद

-प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव

सफल जीवन ऐसे जिएं

पूर्ण जीवन के लिए लुप्त-दुखों से लड़ना सीखें। स्वावलंबनता के लिए एक प्रयासरत्न पकड़ें। लक्ष्य के लिए कटिल. अपने अंदर दया की भावना पैदा करें। अपने विचार को काबूत करें। अपने स्वास्थ्य को संजोंए। दूसरा को अपनाएं।

-हर्ष मोदानवा, उद्योगपति

करंट अफेयर

जेलेंस्की ने पेंसिल्वेनिया में बारूद फैक्टरी का किया दौरा

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अत्यधिक कड़ी सुरक्षा के बीच पेंसिल्वेनिया में गोला-बारूद की उस फैक्टरी का दौरा किया जो रूसी बलों के साथ उनके देश की लड़ाई के लिए आवश्यक हथियारों में से एक का उत्पादन कर रही है। 'स्टौटन सेना गोला बारूद संयंत्र' के निरीक्षण के साथ ही अमेरिका की उनकी यात्रा शुरू हो गयी है और इस दौरान वह युद्ध में यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। वह मंगलवार और बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे तथा फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बृहस्पतिवार को वाशिंगटन में वार्ता करेंगे। जेलेंस्की का काफिला जब रविवार दोपहर को गोला बारूद फैक्टरी की ओर जा रहा था तो यूक्रेनी झंडे लहराते हुए समर्थकों का एक छोटा दल उनकी सराहना के लिए आसपास एकत्र हो गया। फैक्टरी के आसपास के इलाके की सड़क से ही घेराबंदी कर दी गयी थी और वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। स्टौटन संयंत्र देश में उन चुनिंदा केंद्रों में से एक है जो तोपों के 155 एमएम के गोले का उत्पादन करता है और उसने पिछले एक साल में अपना उत्पादन बढ़ा दिया है। यूक्रेन को अमेरिका से पहले ही 30 लाख से अधिक 155 एमएम के गोले प्राप्त हो चुके हैं।

ऑफ बीट

साही के जबड़े के विकास को लेकर बहस समाप्त

'करंट बायोलॉजी' में प्रकाशित हमारे अनुसंधान पत्र में दलील दी गई है कि उत्तरी अमेरिकी साही के पूर्वज एक करोड़ साल पहले के हो सकते हैं, लेकिन वे लगभग 80 लाख वर्ष बाद तक पहचाने जाने योग्य नहीं होंगे। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में साही की अस्थि संरचना की तुलना करके, हमने निर्धारित किया कि उन 80 लाख वर्षों में, उत्तरी अमेरिकी साही अप्रत्याशित रूप से अभी भी अपने करीबी रिश्तेदारों नियोट्रॉपिकल साही की तरह दिखते थे, जो आज उष्णकटिबंधीय मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। आधुनिक उत्तरी अमेरिकी साही अपने कांटेदार रिश्तेदारों के बीच विशिष्ट है। इसकी एक छोटी पूंछ, एक जबड़ा होता है जो पेड़ों से छाल को खुरच सकता है और इसका वजन 10 से 25 पाउंड (4.5 और 11.3 किलोग्राम) के बीच होता है। स्पष्ट रूप से संबंधित होते हुए भी, नियोट्रॉपिकल साही अलग दिखते हैं। उनकी लंबी, पकड़ में आने वाली पूंछ, कमजोर जबड़े होते हैं और उनका वजन 1.5 से 10 पाउंड (0.68 और 4.5 किलोग्राम) के बीच होता है। आधुनिक जानवरों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि ये दोनों समूह लगभग एक करोड़ वर्ष पहले अलग हो गए थे।

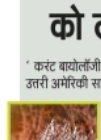

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 188

नई राह पर श्रीलंका!

बीते सप्ताहांत संपन्न हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनावों ने कई पुरानी मिसाल तोड़ी हैं और देश की दशकों पुरानी राजनीतिक परंपरा को भी उलट दिया। श्रीलंका में आमतौर पर सत्ता दो अलग-अलग शक्तियों के बीच बंटती रही है जिनका नेतृत्व मध्य-दक्षिण और मध्य-वामपंथी दल करते हैं। यहां तक कि पिछले ताकतवर लोगों मसलन राजपक्षे परिवार के राष्ट्रपतियों ने भी इन्हीं दो दलों में से किसी एक से शुरुआत की थी। परंतु नव निर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) से आते हैं। वह श्रीलंकाई राजनीति की वाम और राष्ट्रवादी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसके अलावा दिसानायके को पहली प्राथमिकता वाले मतों में बहुमत नहीं मिला जबकि कार्यकारी राष्ट्रपति के अन्य चुनावों में ऐसा होता रहा है। ऐसा इसलिए हुआ कि वह त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, दिसानायके और सजित प्रेमदासा मैदान में थे। प्रेमदासा और विक्रमसिंघे पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं लेकिन दोनों ही श्रीलंकाई राजनीति के मध्य-दक्षिण धड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा एक समय दबदबा रखने वाली यूनाइटेड नैशनल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि आखिर क्यों दिसानायके दूसरी प्राथमिकता के इतने वोट आसानी से जुटा सके जिससे वह जीतने में कामयाब रहे। प्रेमदासा और विक्रमसिंघे भी पुराने राजनीतिक परिवारों से हैं और पूर्व राष्ट्रपतियों से जुड़े हैं। दिसानायके एक बाहरी व्यक्ति हैं और श्रीलंका की राजनीति में यह भी कम अस्वाभाविक बात नहीं।

सवाल यह है कि क्या दिसानायके उसी तरह देश चलाएंगे जैसा कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान में कहा था: एक बाहरी विद्रोही के रूप में। जरूरी नहीं कि यह श्रीलंका के लिए अच्छी खबर हो। देश की अर्थव्यवस्था दो साल पहले की उथलपुथल के बाद कुछ हद तक स्थिर हो चुकी है। उस समय तो देश लगभग डिफॉल्ट जैसे हालात का शिकार हो गया था। परंतु देश अपने कर्ज के भारी बोझ को लेकर सही ढंग से नहीं निपट सका है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था को जो नया अवसर दिया है उसे लेकर घरेलू स्तर पर बहुत अधिक विवाद है। माना जा रहा है कि उसकी शर्तों में जो खर्च कटौती शामिल है उसकी वजह से देश में गरीबी बढ़ी है। विश्व बैंक का भी यही अनुमान है। दिसानायके के चुनाव से जुड़ी यही इकलौती चिंता नहीं है। उन्होंने खुद को और अपने दल जेवीपी को नए सिरे से पेश किया है लेकिन लंबे समय तक इनका जुड़ाव न केवल किसान विद्रोह की माओवादी विचारधारा से रहा है बल्कि सिंहली राष्ट्रवाद से भी उनका जुड़ाव रहा है। उनका प्रचार अभियान काफी हद तक इस अतिवादी क्षेत्र को दी जानकारियों पर भी आधारित रहा जिसमें यह बात भी शामिल रही कि वे श्रीलंका की शक्तिशाली सैन्य लॉबी को युद्ध अपराधों की जांच से भी बचाएंगे।

यह भी माना जाता है कि उनकी पार्टी भारत के बजाय चीन को लेकर बहुत अधिक सहज है। जबकि चीन ने पिछले पूरे दशक श्रीलंका को लगातार अपने पाले में करने का प्रयास किया है। श्रीलंका के ताजा अनुभवों के बाद अब देखना होगा कि यह रिश्ता कैसे आगे बढ़ता है।

भारत ने दिसानायके तक तत्काल पहुंच बनाने का प्रयास किया है और वह उन्हें संदेह का लाभ देना चाहता है। वह गत वर्ष भारत आए थे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले थे। नए राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण का नए सिरे से परीक्षण किया जाएगा और उन्होंने यह संकेत भी दिया है कि वह निर्यात को बढ़ावा देने और आर्थिक सुधारों को श्रीलंका की दिक्कतों का टिकाऊ हल मानते हैं।

जहां तक सामाजिक समरसता की बात है तो तीनों उम्मीदवारों में से देश की तमिल अल्पसंख्यक आबादी के साथ सत्ता में साझेदारी के लंबे समय से चले आ रहे वादे को निभाने की सबसे कम उम्मीद उन्हीं से थी। परंतु उन्होंने कम से कम देश की बहुसांस्कृतिक विरासत की तो बात की है। संभव है कि संसदीय चुनाव जल्दी ही होंगे और उन्हें विधायी बहुमत मिलेगा तथा वह अपनी पसंद का प्रधानमंत्री चुन सकेंगे। तब यह स्पष्ट होगा कि देश कैसे आगे बढ़ता है।

अजय मोहंती

जीएसटी सुधार पर दूरदर्शी सोच की दरकार

राजस्व में कमी के डर से जीएसटी दरों को वाजिब बनाने से हिचकना दूरदर्शिता की कमी को दर्शाता है। बता रहे हैं एम गोविंद राव

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में अब कुछ खास नहीं रह गया है। आम तौर पर इनमें जीएसटी दरों में कुछ फेरबदल किया जाता है और फौरी जरूरतों के हिसाब से छोटे-मोटे प्रशासनिक बदलाव किए जाते हैं। मगर कर संरचना में व्यापक सुधार कर इसे श्रेष्ठ बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जाता।

लगता है कि जीएसटी परिषद मानती है कि कर प्रणाली अब स्थापित हो गई है, इससे जुड़े लोग इसके अभ्यस्त हो चुके हैं तथा इसे स्वीकार भी कर चुके हैं। परिषद की बैठकों में निर्णय फौरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं और पूरी कवायद मामूली सुधार तक ही सीमित रहती है। यानी जीएसटी परिषद की बैठक में दीर्घकालिक फैसले नहीं लिए जाते हैं और सोचने एवं निर्णय लेने का दायरा काफी सीमित होता है। दूर तक नजर रखते हुए कर के साथ जुड़ी तीन लागत कम करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जाता। ये लागत हैं - संग्रह पर होने वाला खर्च, अनुपालन पर खर्च और आर्थिक विकृति। इस सोच में राजस्व गंवाने का डर और राजस्व में कमी लाए बगैर बेहतर कर व्यवस्था तैयार करने के लिए बुनियादी शोध की कमी साफ दिखती है।

इसलिए अचरज नहीं हुआ, जब जीएसटी परिषद की 9 सितंबर की बैठक में विदेशी विमानन कंपनियों द्वारा आयात की जाने वाली सेवाओं को छूट, कैंसर की दवाओं और हेलीकॉप्टर यात्रा पर शुल्क में कमी और जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की समीक्षा तथा मुआवजा उपकर के लिए दो अलग-अलग समितियों के गठन का फैसला जैसे मामूली निर्णय ही लिए गए। ये सभी फैसले तात्कालिक जरूरत ध्यान में रखते हुए लिए गए यानी इनके पीछे व्यापक सुधार या भविष्य की जरूरतों की फिक्र नहीं है।

जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त रूप से कारगर नहीं है और यदि राजस्व सुनिश्चित करते हुए इसे प्रतिस्पर्द्धी बनाना है तो बड़े सुधार करने होंगे। भारत को इस सदी के मध्य तक विकसित देश बनने की अपनी अभिलाषा पूरी करनी है तो उसे प्रतिस्पर्द्धी कर प्रणाली चाहिए, जिसके अवांछित परिणाम कम से कम हों। जीएसटी व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए निस्संदेह इसमें सुधार की आवश्यकता है। इससे कर प्रणाली में शामिल वस्तुओं या सेवाओं की संख्या काफी बढ़ जाएगी, दरें कम होंगी, उनमें अंतर भी कम होगा तथा सरल एवं पारदर्शी ढांचा होगा।

ऐसी किसी भी व्यवस्था में करों के साथ जुड़ी तीनों लागतें - संग्रह में खर्च, अनुपालन पर खर्च और आर्थिक विकृति कम से कम होनी चाहिए। कर प्रणाली की दिशा बदलने के लिए यह एकदम सही समय है। बड़े सुधार तभी अच्छी तरह लागू होते हैं, जब अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही होती है क्योंकि इससे राजस्व बढ़ा हुआ ही रहता है।

दुनिया भर में मूल्य वर्द्धित कर (वैट) के अनुभव बताते हैं कि कोई एक मॉडल या ढांचा सबके अनुकूल नहीं हो सकता। प्रत्येक देश ऐसी व्यवस्था अपनाता है, जो उसकी परिस्थितियों के अनुकूल होती है और सभी को स्वीकार्य होती है। फिर भी ज्यादातर देश ऊपर बताई गई तीनों लागत कम रखने के कुछ सामान्य सिद्धांतों पर अमल करते हैं। ज्यादातर कर विशेषज्ञ जिन महत्त्वपूर्ण सामान्य सिद्धांतों का सुझाव देते हैं उनमें कुछ रियायतों एवं अपवादों के साथ वैश्विक कर का लक्ष्य निर्धारित करना, कई लक्ष्य हासिल करने के फेर में पड़ने के बजाय कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य राजस्व सृजन तक सीमित रखना, छोटे करदाताओं के बजाय बड़े करदाताओं को ध्यान में रखकर समुचित ऊंची सीमा तय करना ताकि प्रशासनिक खर्च कम रहे और कराधान में अधिक समानता आए शामिल हैं। इसके अलावा वे प्रशासनिक, अनुपालन एवं विकृति शुल्क कम से कम रखने के लिए सरल संरचना तैयार करने, आवश्यकता से अधिक जानकारी नहीं मांगने, साफ-सुथरा लेखा-जोखा (रिकॉर्ड) रखने की व्यवस्था को बढ़ावा देने और स्वतः-समीक्षा के लिए दीर्घ अवधि का लक्ष्य निर्धारित करने की भी सलाह देते हैं।

वैट से मिले अनुभव यह भी बताते हैं कि राजनीतिक कारणों से या स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए शुरुआत में कुछ खामियां (जैसे काफी ऊंची या काफी कम सीमा, जरूरत से अधिक छूट या कई दर श्रेणियां तैयार करना) रहने दी जाती हैं तो बाद में उन्हें दूर करना आसान नहीं होता।

जीएसटी प्रणाली में सबसे जरूरी सुधार दरों को वाजिब बनाना है और ऐसा तुरंत किया जाना चाहिए। वर्ष 2000 के बाद जिन 31 देशों ने किसी न किसी रूप में वैट लागू किया है, उनमें से 25 ने कर की एक ही दर रखी है। भारत को छोड़कर शायद ही किसी देश में दो से अधिक दरें हैं। दरें ज्यादा होने पर वस्तुओं के वर्गीकरण या उनकी श्रेणी पर विवाद उठते हैं, इनवर्टेड शुल्क ढांचे में विसंगति दिखती हैं, अनपेक्षित बदलाव होते हैं, संसाधन बेवजह आवंटित होते हैं और अनुपालन एवं प्रशासन की इंझट भी बढ़ती है।

जीएसटी प्रणाली में अलग-अलग कर दर से मिलने वाले राजस्व के आंकड़े नहीं दिए जाते मगर कर्नाटक से मिली जानकारी के मुताबिक 2023-24 में 75 प्रतिशत से अधिक राजस्व 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत दर से आया था। मोटा अनुमान है कि दोनों दरों को मिलाकर 15 प्रतिशत की दर लागू करें तो राजस्व पर कोई असर नहीं होगा। इसी तरह 28 प्रतिशत की दर हानिकर वस्तुओं तक सीमित रखें तो निर्माण और यात्री वाहन उद्योगों को अधिक कर के बोझ से मुक्ति मिल जाएगी तथा श्रम के अधिक इस्तेमाल वाले दोनों उद्योगों में सुधार भी होगा। इसके लिए थोड़ा-बहुत राजस्व गंवाना भी पड़े तो उसकी भरपाई कर मुक्त वस्तुओं की सूची छोटी करने और 5 प्रतिशत कर दर को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने से हो जाएगी। इस तरह राजस्व में सेंध लगवाए बगैर कर की केवल दो दरें हो सकती हैं और हानिकर वस्तुओं के लिए अलग दर हो सकती है।

कर प्रणाली को अधिक व्यापक और प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए एक और बड़ा सुधार होना चाहिए और वह है पेट्रोलियम उत्पादों तथा बिजली को जीएसटी के दायरे में लाना। 2019-20 में पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से मिलने वाली रकम की केंद्र के उपभोग कर राजस्व में 29 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। विशेष श्रेणी से बाहर के राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर लगभग 53 प्रतिशत था। अलग-अलग राज्यों में यह भिन्न था जैसे बिहार में 36 प्रतिशत और तेलंगाना में 61 प्रतिशत। पेट्रोलियम उत्पादों एवं बिजली को जीएसटी दायरे से बाहर रखने से निर्यातकों को नुकसान पहुंचता है क्योंकि वे उत्पादन एवं वितरण में इस्तेमाल होने वाले परिवहन पर इनपुट टैक्स शून्य नहीं कर सकते। इसके अलावा कर दायरा संकीर्ण हो जाता है क्योंकि हवाई यात्रा और वातानुकूलित एवं पहली श्रेणी की रेल यात्रा छोड़कर पूरा परिवहन क्षेत्र कर दायरे से बाहर हो जाता है।

परिवर्तन का प्रतिरोध होता ही है और कर प्रणाली में बदलाव का खास तौर पर होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल स्टडीज के पॉल जॉनसन और डेविड माइल्स ने ब्रिटेन में कर सुधार पर जेम्स मिरलिस की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद कहा, 'वास्तविक दुनिया में कर सुधार के प्रस्ताव की राह में राजनीति बड़ी बाधा होती है। कर सुधार से जिन्हें नुकसान होता है वे नाखुशी जाहिर करते हैं और इससे फायदा पाने वाले शुक्रिया तक अदा नहीं करते। इससे कराधान नीति यथास्थिति में ही फंसकर रह जाती है।'

जीएसटी परिषद ने कर संरचना की समीक्षा करने और इसमें बदलाव पर सुझाव देने के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया है। लेकिन इसमें काफी कम प्रगति हुई है, जिसका आंशिक कारण यह है कि ठोस शोध के अभाव में कोई भी राजस्व नहीं गंवाना चाहता। यह कहना ठीक नहीं होगा कि लोग कर संरचना के आदी हो गए हैं और बड़े सुधारों की जरूरत नहीं है। इस सोच का सीधा मतलब है कि विकृतियों के कारण हो रहे अदृश्य आर्थिक नुकसान पर विचार नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है कि करों में बदलाव और जीएसटी को व्यापक बनाने के कदम जल्द ही उठाए जाएंगे।

(लेखक 14वें वित्त आयोग के सदस्य थे। लेख में उनके निजी विचार हैं)

महंगी पड़ रहीं दवाएं तो घर पर खुद ही बनाएं!

सोफोसब्युविर नाम की दवा का इस्तेमाल हेपटाइटिस सी के इलाज में होता है। वायरस से होने वाली यह बीमारी हर वर्ष ढाई लाख लोगों की जान ले लेती है। अमेरिका में गिलियड साइंसेज इसे 'सोवाल्डी' नाम से बेचती है। हेपटाइटिस सी के कई उपचार एक साल तक चलते हैं और इस बीमारी में 70 फीसदी मरीज ठीक हो जाते हैं।

इसके उलट सोवाल्डी की 84 गोलियों वाला 12 सप्ताह का कोर्स करने पर 90 फीसदी मरीज ठीक हो जाते हैं। परंतु सोवाल्डी की एक गोली की कीमत 1,000 डॉलर है यानी 12 सप्ताह के कोर्स का खर्च 84,000 डॉलर है। दिलचस्प है कि इसी दवा की 84 गोलियां केवल 75 डॉलर में भी मिल जाती हैं।

हैरान होने की जरूरत नहीं है। यह डू इट योरसेल्फ (डीआईवाई) यानी खुद ही दवा बनाने से मुमकिन है। इस बाजार की अगुआई कर रहा है फोर थीव्स विनेगर कलेक्टिव (एफटीवीसी)। एफटीवीसी विस्तार से बताता है कि ऑनलाइन मंगाए गए मामूली पुर्जों और वस्तुओं से उपकरण बनाकर घर पर ही केमिकल लैब कैसे लगाई जा सकती है। यह मशीन लर्निंग प्रोग्राम केमहैकिटका डाउनलोड करने की सुविधा भी देता है। इस तरह रसायनों का इस्तेमाल कर कई प्रकार की दवाएं घर पर ही बनाई जा सकती हैं।

इंटरनेट की तरह केमहैक्टिका एमआईटी-डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के प्रोजेक्ट आस्कोस का ही एक रूप है। इसने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर मॉलिक्यूल बनाने के रास्ते बताता है। यह देखता है कि कितनी रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं और उनमें से मॉलिक्यूल तैयार करने की सबसे सस्ती प्रतिक्रिया बताता है। यह संभावित रसायन सुझाता है और आसानी से मिलने वाले रसायन को इंटरनेट पर ढूंढ भी देता है।

एफटीवीसी ने 'माइक्रो लैब' तैयार की है, जो आसानी से ऑनलाइन मिलने वाले पुर्जों और हिस्सों से बना ओपन सोर्स नियंत्रित लैब रिएक्टर (सीएलआर) है। यह प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल होने वाले सीएलआर का डीआईवाई संस्करण है। एफटीवीसी कई मैनुएल, सर्किट बोर्ड और डाउनलोड होने वाले सॉफ्टवेयर बनाता है, जिनका इस्तेमाल माइक्रोलैब द्वारा किया जा सकता है। माइक्रो लैब प्रतिक्रिया के लिए इन रसायनों को डालती है, तापमान तय करती है, रसायन मिलाती है और ऐसे कई काम करती है। एफटीवीसी पर एक किताब 'एपोथिकेरियम' भी है, जिसमें कुछ दवाएं बनाने के फॉर्मूले और तरीके दिए गए हैं।

देवांशु दत्ता

इसका इस्तेमाल किया जाए तो वाणिज्यिक यानी बड़े पैमाने पर दवा बनाने में जो खर्च होता है, उससे बहुत ही कम खर्च में कम मात्रा में दवा बनाई जा सकती है। कई बार दवा की किल्लत होती है या दवा मिल ही नहीं रही होती। एफटीवीसी खुद ही एपिफेन बनाने की सुविधा भी देता है। एपिफेन इंजेक्टर होता है, जिसकी मदद से किसी दवा की तय खुराक शरीर के भीतर पहुंचाई जा सकती है।

दूसरी परिवीजना में एफटीसवची ने हेरोइन विक्रेताओं को उसमें ऐसी दवा मिलाने के लिए मना लिया, जिसके बाद सड़क पर हेरोइन लेने वालों में एचआईवी संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। इससे सबको फायदा हो रहा है। नशा बेचने वाले खुश हैं कि उनके ग्राहक मर नहीं रहे और एक ही सुई का कई लोगों द्वारा इस्तेमाल करने के बाद भी एचआईवी संक्रमण के बहुत कम मामले आ रहे हैं।

एफटीवीसी का वैज्ञानिक पक्ष मजबूत है। टीवी शो ब्रेकिंग बैड में रसायन विज्ञान का एक शिक्षक मेथमफिटामाइन बनाने के लिए खुद ही लैब बना लेता है। एफटीवीसी का शोध और विकास भी इसी तरह योग्य केमिस्ट करते हैं। वे पर्चे पर मिलने वाली दवाओं की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं यानी उनमें मौजूद सामग्री और बनाने के तरीके समझ लेते हैं। एफटीवीसी इस परियोजना को 'द राइट टु रिपेयर द बॉडी' कहता है। इसके तहत महंगी दवाओं को निजी इस्तेमाल के लिए तैयार करने के सस्ते रास्ते तलाशे जाते हैं। इसके लिए आम रसायनों और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। दवा कंपनियों के उलट एफटीवीसी दवाओं की नकल करने पर होने वाले कानूनी झंझटों की फिक्र नहीं करता और न ही बड़े पैमाने पर दवा बनाना चाहता है। यह दवा बनाने की पूरी जानकारी मुफ्त में देता है।

दवाएं उनमें शामिल सामग्री के मुकाबले बहुत महंगी इसलिए भी होती हैं क्योंकि दवा कंपनियों को अपना निवेश वापस वसूलना होता है। नई दवा बनाने में बहुत खर्च होता है। उसका व्यावसायिक यानी बेचने के लिए उत्पादन करने से पहले शोध एवं विकास, परीक्षण, पेटेंट आदि की प्रक्रिया होती है। पेटेंट वाली दवाओं पर जो प्रीमियम मिलता है, उसे देखकर ही कंपनियों को नई दवाएं तैयार करने का हौसला मिलता है।

परंतु पेटेंट प्रणाली का दुरुपयोग संभव है और इसके कारण कम गुणवत्ता वाली दवाएं भी बन सकती हैं। दवाओं के शोध एवं विकास में अक्सर उन बीमारियों पर ध्यान दिया जाता है, जो अमीरों को ज्यादा होती हैं। वायग्रा और ओजेम्पिक में मलेरिया की दवा से अधिक मुनाफा मिलता है। कोई भी बड़ी औषधि कंपनी नए एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए शोध पर पैसे खर्च नहीं करती। इसी कारण ऐसे बैक्टीरिया दुनिया भर को चपेटमें ले रहे हैं, जिन पर एंटीबायोटिक्स का असर ही नहीं होता।

दवा कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए अपनी मर्जी से दाम करती हैं, जो उनके हिसाब से बाजार में मिल सकते हैं। सोवाल्डी जैसे उदाहरण बताते हैं कि उत्पादन में होने वाले खर्च और कीमत में बहुत अधिक अंतर है। मगर सार्वभौमिक सरकारी स्वास्थ्य सेवा वाले देश जैसे यूरोपीय संघ या स्वास्थ्य बीमा वाले देश मसलन भारत अथवा अमेरिका इनमें से कुछ दवाएं खरीदते हैं।

डीआईवाई के जरिये तैयार दवाओं के साथ कानूनी दिक्कतें हैं और गुणवत्ता के कारण कई बार ये बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। परंतु एफटीवीसी की विज्ञान पर मजबूत पकड़ और दवा बनाने का विस्तृत ब्योरा चिंताओं को कम कर देता है। जहां डॉक्टरी पर्चे पर ही मिलने वाली दवाओं की किल्लत हो, वहां डीआईवाई दवाएं जीवन रक्षक हो सकती हैं। अमेरिका के कुछ राज्यों में आपातकालीन गर्भनिरोधक इसका उदाहरण हैं।

अवैध डीआईवाई दवाओं का असर बाजार पर भी दिखता है। अधिकतर लोग प्रयोगशाला लगाकर खुद दवा बनाने का झंझट करने के बजाय दुकान से दवा खरीदना पसंद करते हैं। परंतु डीआईवाई के कारण कीमतों पर लगाम कस जाती है। अगर पर्चे पर मिलने वाली दवा बहुत ही कम कीमत में घर पर भी बनाई जा सकती है तो लोग उसे खुद ही बनाना पसंद करेंगे।

आपका पक्ष

क्वाड के बहाने चीन पर लगाम कसने की कवायद

अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2017 में एशिया-प्रशांत में साझा सुरक्षा के लिए चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) की शुरुआत की थी। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन अपना दबदबा बनाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए क्वाड के सहारे चीन का सैन्य एवं आर्थिक प्रभाव कम करने की कोशिश जारी है। चीन की विस्तारवादी सोच के कारण क्वाड देश एकजुट हुए हैं और इसके जरिये चीन पर दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है। एशिया-प्रशांत सागर में चीन ने अपनी नौसेना को नियुक्त कर रखा है तथा वह समुद्री माल परिवहन में बाधक बनने की कोशिश करता रहता है। इसके जवाब में क्वाड देशों ने मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग (मैत्री) योजना लाई है। एशिया-प्रशांत सागर में क्वाड देशों के सदस्य कई बार समुद्री अभ्यास कर चीन को करारा जवाब भी दे चुका है। समुद्र पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए तथा समुद्री मार्ग हर किसी देश के लिए होना चाहिए। समुद्र के जरिये माल परिवहन की लागत कम होती है और अधिकांश वैश्विक व्यापार इसी से होता है। आज के युग में वैश्विक व्यापार से देश को आर्थिक मजबूती तो मिलती ही है साथ ही तकनीक का भी आदान-प्रदान भी होता है। चीन पर लगाम कसने के लिए क्वाड देशों की पहल सराहनीय है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज व जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा

मुफ्त की घोषणाओं पर रोक लगाए चुनाव आयोग

मुफ्त की चुनावी रेवड़ियां बांटने की होड़ ने राज्यों की आर्थिक स्थिति को पंगु बना दिया है। चुनाव आयोग को दलों की ऐसी घोषणाओं पर रोक लगानी चाहिए। रेवड़ी और सब्सिडी के बांटों को तभी पूरा किया जा सकता है, जब राज्य निवेश और औद्योगीकरण के माध्यम से राजस्व बढ़ाने का प्रयास करें।

रामबाबू सोनी, इंदौर

खर्च और आय के बीच संतुलन बनाए राज्य सरकारें

वित्तीय संकट से बचने के लिए राज्य सरकारों को अपने खर्च और आय के बीच संतुलन बनाना चाहिए। ताकि वे अधिक पैसे न खर्च करे और कर्ज में न डूबे। साथ ही सरकारों को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई कदम उठाने चाहिए जैसे बजट में संतुलन, आर्थिक विकास कर सुधार, सार्वजनिक खर्च, कृषि क्षेत्र में सुधार आदि। राज्य सरकारों को वित्तीय संकट से बचने के लिए अपने राजस्व को बढ़ाना चाहिए। अपने व्यय को कम करने के साथ ही केवल जरूरी कामों पर पैसे खर्च करना चाहिए। राज्य सरकारों को अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए।

रत्नाकर मिश्रा, गोरखपुर

वित्तीय अनुशासन का पालन आवश्यक

राज्य सरकारों को वित्तीय संकट से बचने के लिए अपने अनुत्पादक खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। विधायिका और कार्यपालिका दोनों को वित्तीय अनुशासन का पालन करना चाहिए। कुछ मूलभूत योजनाओं को छोड़कर ऋण की सारी योजनाएं बंद कर देनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के करों की वसूली में गति लानी चाहिए। अनावश्यक अनुदानों को बंद करना चाहिए।

ललित महालकरी, इंदौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से दो रूसी और एक अमेरिकी नागरिक को लेकर सोयूज कैप्सूल सोमवार को कजाकिस्तान में उतरा। इसके साथ ही रूस के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का लंबा प्रवास समाप्त हो गया। ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चूब अंतरिक्ष स्टेशन पर 374 दिन बिताने के बाद वापस लौटे, जो वहां उनका सबसे लंबा निरंतर प्रवास था। इस कैप्सूल में अमेरिकी ट्रेसी डायसन भी थीं, जो छह महीने तक अंतरिक्ष स्टेशन में रहीं।

मोदी का संबोधन

क्वाड की भूमिका

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थायित्व व समावेशी प्रगति प्रोत्साहित करने में 'क्वाड' की महत्वपूर्ण भूमिका है। अमेरिका के विलमिंगटन में आयोजित नवीनतम क्वाड सम्मेलन ने चार सदस्य देशों-भारत, अमेरिका, जापान व आस्ट्रेलिया के बीच खासतौर से राजनीतिक रूप से अस्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र को देखते हुए सहयोग का बढ़ता महत्व रेखांकित किया है। इसमें क्षेत्र में शांति स्थापित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका भी पहचानी गई है। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्र, खुले व समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति समूह की प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए जोर दिया कि सभी क्वाड सदस्य इस प्राथमिकता का साझा करते हैं। साथी नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि शिखर सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा है तथा टकराव हो रहे हैं। इन नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज तथा जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा शामिल हैं। मोदी का संदेश स्पष्ट था कि क्वाड की शक्ति इसके साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के इसके द्वारा समर्थन तथा शांतिपूर्ण विवाद समाधान के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में भारत द्वारा महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग करते हुए अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' बनाए रखने की बात स्पष्ट थी। हिंद-प्रशांत क्षेत्र, खासकर एशिया में बदलती सत्ता संरचनाओं के कारण आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है। अपनी रणनीतिक स्थिति तथा आर्थिक प्रभाव के कारण

भारत स्वयं को एक प्राकृतिक नेता के रूप में देखते हुए समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत की पैरवी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि क्वाड कोई 'विशिष्टतावादी' समूह नहीं है, बल्कि यह खासकर स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, उभरती तकनीकों तथा क्षमता निर्माण में सामूहिक हितों की पैरवी करता है। क्वाड में भारत की भूमिका पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है और वह स्वयं को हिंद-प्रशांत में साझा लक्ष्यों की पैरवी करने वाले प्रमुख देश के रूप में पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगला क्वाड सम्मेलन भारत में 2025 में करने का प्रस्ताव किया है। यह समूह के साथ देश की बढ़ती सहभागिता तथा प्रभाव का एक और प्रमाण है।

विलमिंगटन क्वाड शिखर सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब वैश्विक चुनौतियां, जैसे सप्लाई श्रृंखलाओं में बाधा तथा भू-राजनीतिक टकराव तत्काल अंतरराष्ट्रीय सहयोग की मांग करती हैं। क्वाड के भीतर स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों तथा क्षमता निर्माण में भारत के योबदान ने महत्वपूर्ण साझीदार के रूप में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। क्वाड की प्रगति के साथ ही भारत सहयोगियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हिंद-प्रशांत ऐसा क्षेत्र बना रहे जहां 'कानून के शासन' का सम्मान हो तथा सभी देश समृद्धि का साझा करें। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा एक व्यापक राजनयिक संपर्क का भी अंग है जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन को संबोधित करना शामिल हैं। यह राजनयिक पहल भारत द्वारा शांति, स्थायित्व तथा समावेशी विकास पर वैश्विक संवाद को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने पर केन्द्रित है। विकसित होते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए भारतीय नेतृत्व क्वाड में सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ हिंद-प्रशांत को स्थिरता व साझा समृद्धि का क्षेत्र बनाने के लिए भी प्रतिबद्धता प्रकट करता है।

एकसाथ चुनाव हेतु आवश्यक संशोधन

हालांकि, सहज दृष्टिकोण के लिए अनेक प्रस्ताव हैं, पर कमियां दूर करने के लिए मध्यावधि चुनाव के कारण आने वाली बाधाओं को संबोधित करने वाले सुधार करने जरूरी होंगे।

सुभाष चंद्र अग्रवाल
(लेखक, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं)

हाल ही में केन्द्रीय कैबिनेट ने 'एक देश एक चुनाव' के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति की संस्तुतियां स्वीकार कर ली हैं। हालांकि, इसकी अनेक संस्तुतियां प्रशंसनीय हैं, पर इसके बावजूद कुछ कमियां दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। उल्लेखनीय है कि इस योजना में न केवल लोकसभा और विधानसभाओं, बल्कि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के चुनाव भी एकसाथ कराने की संस्तुति की है। वर्तमान संस्तुतियों के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ कराने के 100 दिन बाद स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के चुनाव कराने होंगे। एक प्रकार से यह एकसाथ चुनाव कराने वाली व्यवस्था से कुछ कम है। एक बार महत्वपूर्ण सुधार के दृष्टिकोण से सभी चुनाव एकसाथ कराना आवश्यक होगा जिसमें स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के चुनाव भी शामिल हों। कोविंद समिति ने एक और मुद्दा बिना समाधान के छोड़ दिया है। यह मध्यावधि चुनाव की समस्या है, जब त्रिशंकु सदन होने के कारण या कोई गठबंधन ध्वस्त होने के कारण राज्य सरकार या लोकसभा अपने पूरे कार्यकाल के बीच में ही भंग हो जाए। इस चुनौती का समाधान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के एक साथ चयन के साथ अध्यक्षों व उपाध्यक्षों या चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से कराने से हो सकता है। इसके लिए एलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों-ईवीएम के साथ 'वोटर वैरीफायेबल पेपर आडिट ट्रेल'-वीवीपैट का प्रयोग किया जा सकता है।

इन चुनावों के लिए कम से कम 34 प्रतिशत सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन जरूरी होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था से स्थायित्व सुनिश्चित होगा क्योंकि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को केवल एक समान प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकेगा, लेकिन अनिवार्य नामांकन के माध्यम से उसी प्रस्ताव से एक वैकल्पिक नेता की व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रक्रिया में मतदान करने से अलग रहने से उस सदस्य का सदन में मताधिकार छिन सकता है, भले ही उसकी सदस्यता बनी रहे। यह व्यवस्था 'एक देश एक चुनाव' पहल क्रियान्वित करने के लिए जरूरी है क्योंकि इससे अक्सर विधानसभाओं या लोकसभा का भंग होना बंद हो जाएगा। इस व्यवस्था के माध्यम से वर्तमान पदाधिकारियों का चयन पुनः किया जा सकता है। इस व्यवस्था को सुचारु रूप से कारगर बनाने के लिए चुनाव उम्मीदवारी के नियमों में भी परिवर्तन जरूरी होगा। उम्मीदवारी के नियमों को देखते हुए, किसी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने अथवा एकसाथ संसद और राज्य विधानसभा की सदस्यता बनाए रखने पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके साथ ही यदि कोई वर्तमान सांसद या विधायक दूसरी सीट से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अपनी वर्तमान सीट से इस्तीफा देना होगा। इससे ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय पैदा हुई थी, जब ओडिशा के मुख्यमंत्री गिरिधर गोमांगो के एक विवादास्पद वोट के कारण सरकार गिर गई थी।

गिरिधर गोमांगो मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करने के बाद भी सांसद बने हुए थे। एक और महत्वपूर्ण सुधार राज्यसभा चुनाव में गोपनीय मतदान सुनिश्चित करने के माध्यम से किया जाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव के लिए भी वीवीपैट से जुड़ी ईवीएम का प्रयोग किया जाना चाहिए। हसके साथ ही संविधान में संशोधन कर विधान परिषदों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। राज्यसभा में केवल ऐसे सदस्यों का नामांकन किया जाना चाहिए जिन्होंने कभी कोई चुनाव न लड़ा हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उच्च सदन या राज्यसभा सचमुच अनुभवी राजनीतिज्ञों की संस्था बनेगी और इसमें सक्रिय राजनेता शामिल नहीं होंगे। 'हितों का टकराव' रोकने के लिए सांसदों या विधायकों को पार्टी में कोई पद लेने या या सामाजिक पद स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

मंत्रिपरिषद में पदों की संख्या को निचले सदन या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए तथा संसदीय सचिव का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए। चुनावों में अपनी जमानत राशि जब्त करा देने वाले उम्मीदवारों को अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। 'उपरोक्त में से कोई नहीं'-नोटा विकल्प को ज्यादा प्रभावी बनाया जाना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से मतदाता सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार कर देते हैं। इस स्थिति को देखते हुए 'नोटा' से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, भले ही इसके कारण ऐसे उम्मीदवार से अधिक मत पाने वाले को उस खास कार्यकाल के लिए विजेता ही क्यों न घोषित करना पड़े। इसके साथ ही विधायी कार्यवाहियों के लिए सांसदों या विधायकों की 'इम्यूनिटी' या विशेषाधिकार के प्राविधान पर पुनः विचार करना चाहिए क्योंकि इसके कारण अनेक समस्यायें पैदा होती रही हैं। कुख्यात 'जेएमएम रिश्वत मामले' में सर्वोच्च न्यायालय दोषी लोगों के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार के कारण कार्रवाई नहीं कर पाया था। संसदीय नियमों को फिर से लिखा जाना चाहिए ताकि संसदीय मानकों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को कठोर दंड दिया जा सके। इसके साथ ही अध्यक्ष की विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त किया जाना चाहिए।

इससे सांसद महेश मांझी जैसे सांसदों को मामूली दंड से मुक्ति नहीं मिलने पाएगी। महेश मांझी अपनी एक महिला मित्र को अपनी पत्नी बता कर सरकारी खर्च पर विदेश ले गए थे। सत्रों के दौरान सदन में मौजूद 'फरार' सांसदों को उस समय तक जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए जब तक विधि अधिकारी उनके खिलाफ लंबित वारंट को लागू न कर दें। इसके साथ ही सदन में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले सांसदों और विधायकों को अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। जार्ज फर्नान्डीज जैसे मामले सामने नहीं आने चाहिए जिनको अपनी स्मृति कमजोर होने के बावजूद राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया था। इससे उम्मीदवारों की न्यूनतम चिकित्सकीय फिटनेस का मामला भी सामने आता है।

सांसदों द्वारा अपनी सभी परिसंपत्तियों की घोषणा अनिवार्य की जानी चाहिए। इसमें उनकी पति या पत्नी के नाम वाली संपत्ति भी शामिल होनी चाहिए। इससे अघोषित अनेक विवाहों वाली स्थिति समाप्त होगी, जैसा कि अभिनेता से सांसद बने धर्मेन्द्र के मामले में हुआ था। सुविधाओं, किराए, सरकारी आवासों तथा अन्य सभी प्रकार के बकाये सांसदों-विधायकों के वेतन या पेंशन से काट लिए जाने चाहिए। पूर्व सांसदों या मंत्रियों के सरकारी परिसर खाली न करने तक उनकी पेंशन रोक देनी चाहिए। इसके साथ ही चुनाव न लड़ने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता अगले पांच साल के लिए समाप्त कर देनी चाहिए। चुनाव सुधारों को गति देने के साथ ही निर्वाचन आयोग का सशक्तीकरण किया जाना चाहिए ताकि वह इन सुधारों का क्रियान्वयन संसद को एक साल की नोटिस पर कर सके। यदि संसद इस समयसीमा में सुधारों को अस्वीकार न करे तो यह मान लेना चाहिए कि संसद ने उन पर अपनी मुहर लगा दी है। चुनावों में काले धन पर रोक लगाने के लिए आयकर कानून में परिवर्तन कर राजनीतिक दलों को मिलने वाले योगदान पर आयकर छूट की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। इसके साथ ही विवादास्पद 'एमपीलैड्स' योजना तत्काल समाप्त कर देनी चाहिए। यह योजना सांसदों और विधायकों को 'स्थानीय विकास' के लिए अलग से फंड की व्यवस्था करती है। अतीत में इसे काफी बढ़ाया गया है। बार-बार आरोप लगे हैं कि इस फंड का ज्यादातर उपयोग कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए होता है। इसके अलावा अनेक सांसदों और विधायकों का यह विवेकाधीन कोष बिना उपयोग के लैप्स हो जाता है। समय आ गया है कि भारत की चुनाव व्यवस्था में व्यापक सुधार कर इसे ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह तथा स्थिर राजनीतिक प्रक्रिया बनाया जाए।

भारत का विविधतापूर्ण सिनेमा परिदृश्य

चैतन्य के. प्रसाद
(लेखक डीईएफ के पूर्व एडीजी हैं)

हाल के वर्षों में, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफ़ॉर्म के उदय ने मनोरंजन के हमारे तरीके को नाटकीय रूप से बदल दिया है। इन प्लेटफ़ॉर्म ने क्लासिक कंटेंट को पुनर्जीवित किया है और क्षेत्रीय रत्नों को मुख्यधारा के मीडिया में पेश किया है, जो वैश्विक दर्शकों के लिए भारत के विविध सिनेमाई परिदृश्य का एक व्यापक स्पेक्ट्रम पेश करता है। इसके अलावा, ओटीटी ने हमारे सामाजिक व्यवहार को बदल दिया है, जो अनौपचारिक चैट से लेकर वर्चुअल सभाओं तक बातचीत का एक केंद्रीय हिस्सा बन गया है। जहाँ पहले लोग और बताओ जैसे सवालों के साथ विनम्रता का आदान-प्रदान करते थे, वहीं आज, सबसे सही जवाब अक्सर नवीनतम सीरीज या फ़िल्म के बारे में होता है जिसे कोई देख रहा होता है। वर्चुअल वॉच पार्टियाँ दोस्तों और परिवारों के लिए लोकप्रिय माध्यम के रूप में उभरी हैं, जो दूर-दूर से जुड़े हुए हैं, वास्तविक समय में देखने के अनुभवों को जोड़ने और साझा करने के लिए। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म विविध स्वादों को पूरा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।

लेकिन लोगों को एक के बाद एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की सदस्यता क्यों लेनी पड़ती है? इसका सरल उत्तर है कंटेंट। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने क्लासिक शो और फ़िल्मों की विशाल लाइब्रेरी बनाई है, जिससे प्रतिष्ठित सीरीज आसानी से सुलभ हो गई हैं। अपनी कहानी और यादगार संगीत के लिए मशहूर मालगुडी डेज़ और शाहरुख खान की पहली फिल्म फौजी जैसे शो बस एक क्लिक की दूरी पर हैं। यह सुलभता दर्शकों को समय में पीछे जाने, यादगार पलों को फिर से जीने और युवा पीढ़ी को दूरदर्शन युग के दौरान भारतीय टेलीविजन को आकार देने वाली कालातीत कहानियों से परिचित कराने की अनुमति देती है। समकालीन रचनाकार भी पुरानी यादों को नई कहानी के साथ मिला रहे हैं। लापता लेडीज़, हीरामंडी, गन्स एंड गुलाब्स, जुबली, बंबई मेरी जान और रॉकेट बॉयज़ जैसी सामग्री आकर्षक कथानक में रेट्रो तत्वों को बुनती है। ये कहानियाँ अक्सर आधुनिक तकनीक से मुक्त सरल समय में सेट की जाती हैं, जो दर्शकों को

आधुनिक दुनिया की अराजकता से राहत प्रदान करती हैं। वे दर्शकों को अतीत में ले जाती हैं, जिससे कहानियाँ समृद्ध और अधिक आकर्षक बन जाती हैं। उदाहरण के लिए लापता लेडीज़ को ही लें। 2000 के दशक की शुरुआत में सेट की गई इस फ़िल्म की कहानी एक खोई हुई दुल्हन के इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन दर्शकों को इसकी आकर्षक सादगी आकर्षित करती है। भूले-बिसरे रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान या डिजिटल फ़ोटो के अभाव में साझा की जा रही दुल्हन की तस्वीर वाले दृश्य दर्शकों को एक अलग युग में ले जाते हैं। ऐसे पल दर्शकों को अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, शायद रेलवे यात्राओं या अपने जीवन के सरल समय के खास पलों को याद करते हुए।

सांस्कृतिक प्रतीकों-रेट्रो फ़ैशन, पुराने विज्ञापन, विंटेज फ़ोन, कार और यहाँ तक कि घरों का उपयोग-पुरानी यादों की भावना को जगाता है। टेप रिकॉर्डर, पुराने कंप्यूटर जैसी रोज़मर्रा की वस्तुएँ और अतीत में लोगों के सामाजिक व्यवहार का तरीका ओटीटी सामग्री के असली अनुभव में योगदान देता है। यह याद दिलाता है कि समाज कितना आगे बढ़ चुका है, साथ ही अतीत की सुंदरता को भी दर्शाता है। यह भावनात्मक जुड़ाव समग्र देखने के अनुभव को समृद्ध करता है और दर्शकों को और अधिक देखने के लिए वापस लाता है। ओटीटी की पुरानी यादों को आकर्षित करने की अपील ने ओटीटी और चिल संस्कृति की लोकप्रियता को भी बढ़ाया दिया है। हाल ही में मनोज तिवारी ने एक ओटीटी शो के लिए मशहूर भोजपुरी सोहर हिंद के सितारे गाया, जो इंटरनेट पर सनसनी बन गया। यह गाना वायरल हो गया, जिसमें हर उम्र के लोगों ने इसे गाया, जिससे पता चलता है कि कैसे सरल समय से जुड़ी सामग्री पीढ़ियों को एक साथ ला सकती है।

अतीत को फिर से दिखाने के अलावा, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म लगातार नई सामग्री जारी करते रहते हैं, अक्सर व्यापक प्रचार प्रयासों के साथ जो कुछ शो को अत्यधिक लोकप्रिय बनाते हैं। प्रीमियर के लिए रेड कार्पेट इवेंट, मीडिया कवरेज और देखने के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ ओटीटी शो की सूचीबद्ध करने वाले लेख सभी सांस्कृतिक उत्साह का हिस्सा बन गए हैं। यहां तक कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जैसे प्रमुख कार्यक्रम भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर स्ट्रीम होते हैं, जो बड़े पैमाने पर दर्शकों को आकर्षित करते हैं।

ओटीटी विविध प्रतिभाओं को भी बढ़ावा देता है। स्वतंत्र फिल्म निर्माता और क्षेत्रीय कहानीकार, जिन्हें पारंपरिक मीडिया में अनदेखा किया जा सकता था, अब उनके पास वैश्विक दर्शकों के सामने अपना काम दिखाने के लिए एक मंच है। इससे भौगोलिक बाधाओं को तोड़ते हुए नई आवाजों और अनूठी कहानियों की खोज हुई है। ओटीटी की कई भारतीय भाषाओं में कंटेंट दिखाने की क्षमता ने क्षेत्रीय फिल्मों और सीरीज को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद की है।

2023 की FICCI-EY रिपोर्ट के अनुसार, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय कंटेंट ने पहली बार हिंदी भाषा के कंटेंट को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा के शीर्षकों की हिस्सेदारी 2021 में 47% से बढ़कर 2023 में 52% हो गई है। मोहनलाल, जूनियर एनटीआर, विजय सेतुपति और फहद फासिल जैसे सितारे, जो कभी क्षेत्रीय उद्योगों तक ही सीमित थे, अब ओटीटी की पहुंच की बदौलत पूरे भारत में घरेलू नाम बन गए हैं। आरआरआर (तेलुगु), पुष्पा (तेलुगु), केजीएफ (कन्नड़), कंतारा (कन्नड़) जैसी फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए नए दर्शक मिले हैं। तमिल सिनेमा में प्रसिद्धि पाने वाले विजय सेतुपति जैसे अभिनेता जवान और मेरी क्रिसमस जैसी फिल्मों में दिखाई देकर अखिल भारतीय सितारे बन गए हैं। महामारी के कारण तीव्र हुआ यह अंतर-सांस्कृतिक सम्मिश्रण, विविध विषय-वस्तु की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

आप की बात

कांग्रेस की परेशानी

तेजी से बदले घटनाक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हिसार से सांसद कुमारी शैलजा अचानक हरियाणा की राजनीति की केंद्र में आ गई है। अखबारों की सुर्खियों और टीवी न्यूज़ की डिबेट में यह खबर जोरों से चल निकली है कि कुमारी शैलजा न केवल नाराज है, बल्कि कांग्रेस के चुनावी प्रचार से अलग हो गई है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर है। इससे पूर्व भी दलित चेहरा एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में शामिल हो गए थे। हरियाणा का दलित समाज भी इस बात से बेहद नाराज है कि एक तरफ कुमारी शैलजा के प्रति अपमानजनक व अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है, वहीं कांग्रेस के क्षेत्रीय नेतृत्व ने कुमारी शैलजा को अलग-अलग कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कुमारी शैलजा प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कैबिनेट में शामिल थीं, लेकिन इसके बाद कांग्रेस में उनको समुचित अवसर नहीं दिया गया। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को भुनाने की पूरी तैयारी की है और कांग्रेस को दलित-विरोधी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके कारण कांग्रेस को जवाब देना भारी पड़ रहा है। हरियाणा में 21 प्रतिशत दलित हैं जिनकी नाराजी कांग्रेस की जीत के दावों पर पानी फेर सकती है। यहां बसपा और चंद्रशेखर भी सहयोगियों के साथ मैदान में हैं।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

सुनीता पर संकट

सुनीता विलियम्स के आठ दिवसीय अभियान को 8 महीने होने को हैं। अंतरिक्ष का खान-पान रहन-सहन सब एकदम अलग है। सुनीता विलियम्स एक जांबाज महिला की तरह जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। जब तक वह सकुशल धरती पर नहीं लौट आती तब तक मृत्यु के मुख में ही है। यह एकदम नई परिस्थितियों में नई तरह का संघर्ष है। आमतौर से नासा वैज्ञानिक भी किसी इंसान के इतने महीने तक अंतरिक्षयान के जीवन पर भेजने की रिस्क नहीं उठाते। जैसे दुनिया में अनेक आविष्कार अनजाने हो गए, वैसे ही अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय यान के भीतर बिताने का खतरों से भरा अभियान भी सुनीता विलियम्स के वापस धरती पर सकुशल लौट आने पर पूरा होगा। सुनीता विलियम्स पर आया यह संकट अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले बड़बोले निजी क्षेत्र, उससे जुड़े वैज्ञानिकों तथा आर्थिक स्पांसरों के लिए भी सबक है। आखिर अंतरिक्षनाविकों की सुरक्षित व समय पर वापसी की गारंटी किए बिना ऐसा जोखिम क्यों उठाया गया? विडंबना है कि अमेरिका सरकार व दुनिया भर के वैज्ञानिक निजी क्षेत्र के इस दुःसाहस के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। किसी प्रकार के प्रयोग में मानव जीवन की सुरक्षा अनिवार्य है।

- सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

रेलें उलटने का षडयंत्र

देश भर में रेलों को डिरेल करने की साजिश दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब रेल पटरियों पर अवरोध या विस्फोटक रखकर रेलों को दुर्घटनाग्रस्त करने के षडयंत्र सामने न आते हों। अराजक या अपराधी तत्वों का दुस्साहस एक राष्ट्रीय समस्या बनता जा रहा है। रेलों के दुर्गम, जनहीन व जंगली क्षेत्रों से गुजरने तथा विशाल नेटवर्क होने के कारण इनसे निपटने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था तथा रेल पटरियों की सुरक्षा के लिए कदम-कदम पर सुरक्षाकर्मी नियुक्त करना आसान नहीं है। ताज्जुब है कि इन राष्ट्र-विरोधी तत्वों के खिलाफ देश का विपक्ष चुप्पी साधे रखता है, जबकि वह अन्य छोटी-मोटी घटनाओं पर सरकार की आलोचना करता रहता है। समय आ गया है कि ऐसी आतंकी गतिविधियों से कोई समझौता न किया जाए, रेल पटरियों की यथासंभव कैमरों से निगरानी हो, मुखबिरों का नेटवर्क मजबूत किया जाए तथा रेल पटरियों पर अवरोध या विस्फोटक सामग्री रखने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जाए। सैकड़ों-हजारों जनता के जीवन को संकट में डालने वाले अपराधी अधिकतम दंड के अधिकारी हैं। सैनिक ट्रेन उलटने का प्रयास गंभीरतम देश-द्रोह के सिवा और कुछ नहीं है।

- सुधाकर आशावादी, मेरठ

परिवहन क्रांति के दुष्प्रभाव

परिवहन क्षेत्र में आज क्रांति से सड़कों पर चार पहिया वाहनों की भारी भीड़ नजर आती है। एक से बढ़कर एक महंगी कारें सड़कों पर दौड़ती है। इन कारों की ड्राइविंग और उनमें सफर करने वालों के लिए तो एयरबैग जैसी सुविधा देकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है, मगर फुटपाथ और सड़कों पर चलने वाले लोगों की जान का कोई मोल नहीं है। सड़कों पर बहुत तेज गति से रांग साइड चलने या सड़क किनारे घरों और दुकानों में घुस जाने वाली महंगी कारों से अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती है। कहीं राह चलतों को रौंद दिया गया तो कहीं दोपहिया वाहन चपेट में आ गए। रोज सड़क दुर्घटनाओं में अनेक मौतों के बावजूद कड़ी कार्रवाई के अभाव में दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछली सरकार में नितिन गडकरी ने दुर्घटनायें रोकने का अत्यन्त कठोर कदम उठाया था, पर लोकतंत्र में भीड़तंत्र हावी होने के कारण सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। दुर्घटनाओं को देखते हुए शहरों में गति सीमा पर कठोर नियंत्रण लगाने, तत्काल आर्थिक दंड तथा वाहन व ड्राइविंग लाइसेंस जब्ती के कठोर नियम जरूरी हैं।

-अमृतलाल मारू, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 24 सितंबर 2024

कोई लूपहोल न रहे

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पर सोमवार को सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर खुद मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने ऐतिहासिक बताया है तो यह बेवजह नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने न केवल मद्रास हाईकोर्ट के संबंधित फैसले को पलट दिया बल्कि इस अपराध से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर बड़ी बारीकी से और उतने ही विस्तार से चर्चा की। यही नहीं, इस अपराध को देखे जाने के प्रचलित नजरिए में गंभीर संशोधन की जरूरत बताते हुए कोर्ट ने संसद को यह सुझाव भी दिया कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के बदले 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' का इस्तेमाल किया जाए।

ढीला-ढाला रवैया | इस अपराध को लेकर समाज के एक हिस्से में किस तरह का ढीला-ढाला रवैया अपनाया जाता है इसका कुछ अंदाजा मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले से भी होता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। हाईकोर्ट ने 28 साल के व्यक्ति के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के वीडियो डाउनलोड करना या देखना अपने आप में अपराध नहीं। कोर्ट का यह भी कहना था कि आजकल बच्चों में पॉर्न देखना एक बड़ा मसला है और इन्हें दंडित करने के बजाय शिक्षित करने की जरूरत है।

AI image

बाल पॉर्नोग्राफी पर अहम फैसला

स्वतंत्र उपधाराएं | सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के विक्टिमाइजेशन से जुड़े पहलुओं को अहमियत देते हुए इस मसले को देखा और समझा कि हाईकोर्ट के नजरिए में गंभीर खामियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के वीडियो डाउनलोड करता है, देखता है और उसे डिलीट करने या रिपोर्ट करने में नाकाम होता है तो कानून के तहत उस पर केस बनता है। यह भी स्पष्ट हुआ कि इस कानून की धारा 15 के तहत आने वाली उपधाराएं (1), (2) और (3) एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यानी कोई मामला अगर किसी एक उपधारा के दायरे में नहीं आता तो भी वह दूसरी उपधारा के अंतर्गत आ सकता है।

फर्क है अहम | समाज के एक बड़े तबके में पॉर्न वीडियो का फैलाव बढ़ गया है जो एक बड़ी समस्या है। इस वजह से इस तरह के डर की भी गुंजाइश बनती है कि अगर किसी के वट्सऐप पर कोई आपत्तिजनक वीडियो आता है जो डिलीट होने से रह जाता है तो कहीं संबंधित व्यक्ति को अपराधी न मान लिया जाए। मगर यहां वीडियो आने और उसे डाउनलोड करने और देखे जाने का फर्क याद रखने लायक है।

नजर की बारीकी | सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की खासियत यह भी है कि इसने कानूनी दृष्टि को वह बारीकी दी है जो ऐसे आपराधिक मकसद वाले मामलों को अन्य मामलों से अलग कर सके और अपराधियों को 'शिक्षित' करने की जरूरत की ढाल न लेने दे।

धूप-छांव

टूटी उम्मीदों का ग़म

प्रणव प्रियदर्शी

'**फल हमें** मीठा या कड़वा लगता है। सो फल ही हमें चाहिए होता है और फल से ही हम गुस्सा, खीझ और फ्रस्ट्रेशन की इंतिहा पार करने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। वजह फल के स्वाद में है। अगर फल मनचाहा स्वाद देता है तो हम तृप्त महसूस करते हैं, पर अगर यह फीका हो तो मन असंतोष की गवाही देने लगता है। इस असंतोष की मात्रा और तीव्रता फल के स्वाद की घटती क्वॉलिटी के साथ बढ़ती जाती है। लेकिन कल्पना करें कि फल भी वह न हो, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हों। हमें उम्मीद आम की हो और फल मिले बेल का। और, अगर बेल भी न मिले, करेला या नीम सामने आ जाए तो?

सीधा सवाल यह बनता है कि पेड़ कौन सा है? अगर हम नीम के पेड़ से आम की उम्मीद कर रहे हों, बबूल के पेड़ से अमरूद चाहते हों तो भला पेड़ या फल की क्या गलती? पेड़ रातोरात बदल तो नहीं जाएगा? सवाल यह है कि हमने अपने बगीचे में बीज कौन सा डाला? जिस पौधे को सींच-सींच कर बड़ा किया, वह कौन-सा था? अगर वह आम का नहीं था तो फिर बेचारा आम कहां से देगा? हम जितना भी कोसें, वह लाचार, मजबूर-सा अपनी जगह खड़ा रहेगा। हमारे सारे इल्जाम सुनता रहेगा। सारी फटकार, सारी गालियां सहन करता रहेगा। सब कुछ सुनकर भी अगले मौसम में फल वही देगा, जो अभी तक देता रहा है, जो दे सकता है। लेकिन हममें इतना धैर्य कहां कि पेड़ की सुनें, उसकी मजबूरी को समझें। हमें तो फल से मतलब होता है और मतलब होता है अपनी उम्मीदों से। उन टूटी उम्मीदों का गम सारी बातों पर भारी पड़ता है। घर-परिवार, आस-पड़ोस, देश-समाज – हर जगह यही कहानी दिखती है। बोते समय ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन फल पर हाय-तौबा मचाएंगे।'

इतना लंबा-चौड़ा आख्यान सुनना आसान नहीं था। सामान्य स्थिति होती तो कबका वहां से हट चुका होता। मगर बोलने वाले का व्यक्तित्व, सुनने वालों का सम्मोहन और इन दोनों से उपजा माहौल का आकर्षण-वहां से हटना मुश्किल बनाए हुए थे। वहां मौजूद बाकी लोगों के मन में क्या चल रहा था, पता नहीं। पर मेरा मन निरंतर सवाल किए जा रहा था कि 'क्यों बैठा है यहां? ऐसे टाइम वेस्ट करने का भला क्या मतलब है? ये विशुद्ध बातें हैं, बातों से क्या बनता है भाई आजकल?' मन के इन सवालों से आजिज-सा उठने को हुआ कि मन ने ही टोका, 'बेटे, कहां भाग रहे हो? भाग कर जाओगे कहां? देखो तो सही, परिवार, मित्र, परिचित तुम्हारी पूरी दुनिया तो यहीं बैठी मगन है। यह भी एक तरह का फल ही है जिसे तुम सबने बोया-सींचा है। इसे महज बतोलेबाजी कह कर तुम यहां से निकल जाओगे?'

बोल वचन

वह तो बड़े सूम हैं

राहुल पाण्डेय

हम दर्जन भर भाई-बहनों में सिर्फ एक भाई था जो चुप्पा, घुन्ना, काइयां, कंजूस और चालबाज था। हम सभी उसे सूम कहकर चिढ़ाते। वह चिढ़ता और फिर चुप बैठकर इस बात की साजिश करता कि किस-किस से कैसे-कैसे बदला लेना है। भाई-बहनों की दुनिया से बाहर भी ऐसे ढेरों लोग मिले, जो सूम थे, मगर जिन्हें कभी सूम कहने की हिम्मत नहीं हुई। सूम का जो सबसे पहला अर्थ निकलता है, वह है कंजूस। और कंजूस के बारे में यह तो माना ही जाता है कि वे चुप्पे होते हैं, काइयां होते हैं। इन दो गुणों की अनुपस्थिति में कोई सूम बन भी नहीं सकता। लेकिन सूम सिर्फ कंजूस ही नहीं होते हैं। सूम का अर्थ दूध, चांद, लहसुन और पानी से लेकर आसमान और स्वर्ग तक फैला हुआ है। ब्रज में सूम कंजूस के अलावा दूध और स्वर्ग भी होता है। बघेली में सूम सिर्फ पैसा बचाने वाला कंजूस नहीं होता, बल्कि पैसा देकर वापस ले लेने वाला कृपण भी होता है। यानी कंजूस के साथ-साथ वह लालची भी होता है। यही सूम गड़वाल पहुंचकर सोम या सोमड़ी हो जाता है, अर्थ वही कंजूसी वाला ही रहता है। सूम को लेकर ढेरों कहावतें भी हैं। मसलन, सूम का कुत्ता न जाए, न जाने दे। यानी कंजूस के कारिंदे भी किसी को देख नहीं सकते, क्योंकि वे भी सूम ही हो जाते हैं। अब इतने सारे अर्थों को जिस फराखदिली के साथ सूम ने धारण कर रखा है, इसके लिए अंग्रेजी का शब्द miser अकेले काफी नहीं है। बल्कि कहना तो यह चाहिए कि हमारे सूम के सामने अंग्रेजी खुद ही कंजूस हो गई है।

AI image

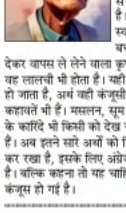

अमेरिका में फेडरल रिज़र्व के ब्याज़ दरों में कटौती करने के बाद भारत में कम हो सकती हैं दरें

US में लोन सस्ता, भारत में मार्केट का क्या

नीलकंठ मिश्रा

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व (भारत में RBI वैसी ही संस्था है) ने पिछले हफ्ते ब्याज दरों में कटौती के चक्र की शुरुआत कर दी, जिसका काफी समय से इंतजार था। उसने ब्याज दरों में आधा फीसदी की कमी की है।

क्यों घटी दरें | अमेरिका में मौद्रिक नीति में बदलाव क्यों आया? फेडरल रिजर्व के दो दायित्व हैं। पहला, अधिकतम रोजगार के लायक हालात बने रहें। दूसरा, महंगाई दर एक दायरे में रहे। फेडरल रिजर्व ने बताया कि दोनों जिम्मेदारियों को लेकर अभी जो रिस्क है, वह करीब-करीब संतुलित है। महंगाई घट रही है, लेकिन रोजगार में कमी आ रही है।

महंगाई और घटेगी | दुनिया के शेयर बाजारों की नजर भी फेडरल रिजर्व पर रहती है। उसकी कमिटी के मेंबर जो आर्थिक अनुमान पेश करते हैं, वह उनके पिछले अनुमानों से कैसे अलग है, बाजार इसे देखकर अपना रास्ता तय करता है। तो इस बार इन मेंबरों ने जो अनुमान पेश किए हैं, उनमें 2024 और 2025 के लिए महंगाई दर के मौजूदा लेवल से नीचे रहने की बात कही गई है।

बेरोजगारी बढ़ेगी | दूसरी ओर, इस साल के अंत और अगले साल में बेरोजगारी दर बढ़ने की आशंका है। 2024 में उन्होंने बेरोजगारी दर का अनुमान 4.4% का रखा है, जबकि अगले साल के लिए भी इसके 'सामान्य' से ऊपर रहने का डर है। अभी यह 4.2% के करीब है। इसलिए इस साल के बचे हुए महीनों और अगले साल में ब्याज दरों में और कमी किए जाने की संभावना है।

बाजार का रिएक्शन | वित्तीय बाजार अक्सर भविष्य का अंदाजा लगाकर उसी हिसाब से अपनी चाल तय करते हैं। फेडरल रिजर्व ने पिछले हफ्ते ब्याज दरों में जो कमी की, उसका उसे पहले से अंदाजा था। इसलिए इस कदम के बाद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊपर गए, जबकि उन्हें नीचे आना चाहिए था। दूसरी ओर, शेयर बाजार के बढ़ने की आशा थी, लेकिन वे मामूली गिरावट के साथ बंद हुए।

भारत पर असर

- भारतीय अर्थव्यवस्था की गति तेज होगी
- वित्तीय तंत्र में बढ़ सकती है नयी सप्लाई
- डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जारी रख सकते हैं निवेश

ग्रोथ पर आशा | फेड ने कम महंगाई दर और स्टेबल ग्रोथ का जो अनुमान पेश किया, उसे 'Goldilocks' सिचुएशन कहा जाता है यानी इकॉनमी संतुलित और महंगाई दर में कमी का लक्ष्य ग्रोथ पर प्रभाव डाले बगैर हासिल किया जा सके। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने 2024, 2025 और 2026 में GDP ग्रोथ के 2% के अनुमान को बनाए रखा है, जो ज्यादा ही आशावादी लगता है।

सरकार का सहारा | पिछले साल अमेरिकी इकॉनमी की रफ्तार अच्छी रही, लेकिन इसे सहारा मिला सरकारी खर्च बढ़ने से। इसी वजह से अमेरिका के फिस्कल डेफिसिट (राजकोषीय घाटे) में बढ़ोतरी हुई। इसलिए अधिक ब्याज दरों से फेडरल रिजर्व महंगाई दर में जिस तरह से कमी लाना चाहता था, उसमें उसे दिक्कत हुई।

ग्रोथ पर दबाव | हमें लगता है कि हाल में अमेरिकी ग्रोथ में जो कमी आई है, वह आगे भी जारी रहेगी। इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। इससे राजकोषीय संतुलन के लिहाज से अमेरिका की चुनौतियां बढ़ेगी। इन हालात में यह सवाल भी बना रहेगा कि मंदी से बचते हुए अमेरिका में ब्याज दरें किस हद तक कम की जा सकती हैं।

कर्ज बहुत सस्ता नहीं | फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया है कि अगले दो वर्षों में वह ब्याज दरों में 2% की कटौती करेगा, लेकिन हमें लगता है कि जिस रेट पर लोगों और बिजनेस को कर्ज मिलता है, उसमें मौजूदा स्तर से बहुत कमी नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि ये दरें लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड की यील्ड से निर्धारित होती हैं और इनमें बिना मंदी के मौजूदा स्तरों से बहुत गिरावट की उम्मीद नहीं है। बॉन्ड यील्ड के ऊपर रहने का कारण अमेरिकी सरकार का ऊंचा डेट और GDP रेश्यो रह सकता है।

दुनिया पर प्रभाव | चीन और यूरोप जैसे कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की है। उसकी वजह यह है कि वैश्विक वित्तीय बाजार में डॉलर का दबदबा है और अमेरिका में मौद्रिक सख्ती खत्म होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फाइनैंशल कंडिशंस में बदलाव की शुरुआत हो गई है।

भारत पर असर | अब आइए देखते हैं कि अमेरिका में हुए इस बदलाव का भारतीय बाजार पर क्या असर होगा? पिछले कुछ महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ सुस्ती आई है। इसके तीन कारण हैं। पहला, आम चुनाव की वजह से केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से खर्च में बढ़ोतरी नहीं हुई। दूसरा, इकॉनमी में मनी सप्लाई की ग्रोथ में बड़ी गिरावट आई है। तीसरा, वैश्विक मांग के कमजोर पड़ने और चीन की वजह से निर्यात क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा है।

यूं हल निकलेगा | समय के साथ सरकारी खर्च बढ़ने से पहली मुश्किल हल हो जाएगी। इसके शुरुआती संकेत दिखने भी लगे हैं। दूसरी समस्या इस डर की वजह से थी कि मनी सप्लाई बढ़ने से स्टॉकमार्केट के कारण करेंसी में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। लेकिन पिछले दो महीने से भी अधिक समय में रिजर्व बैंक ने ओवरनाइट मनी सप्लाई को सरप्लस बनाए रखा है। इससे उसने आने वाले वक्त को लेकर बदले रुख का संदेश भी दे दिया है।

यहां भी दरें कम होंगी | भारतीय वित्तीय बाजार से अभी तक दरों में कमी के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व के दरों में कटौती करने के बाद रिजर्व बैंक के लिए इस सिलसिले में आगे कदम बढ़ाने का मौका हो सकता है। इससे शेयर बाजार को सपोर्ट मिलना चाहिए। साथ ही, अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी पैसा लगा रहे हैं, इसलिए भारतीय बाजार का वैल्यूएशन भी ऊंचा बना रह सकता है।

(लेखक एक्सिस बैंक के चीफ इकॉनमिस्ट हैं)

दस का तीस, दस का तीस में अक्खा इंडिया

नमिता जोशी

अपुन को ठंडा खेल खेलना है, ठंडा खेल, समझा क्या? जा अपुन के वास्ते टिकट का जुगाड़ करके आ वरना तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलेगा अपुन? ये सुनके चिरकुट डरा तो बिल्कुल नहीं, बस अपने टिंड को मंकी के माफिक खुजाने लगा। अपुन पूछ लिया, काइकू सिर खुजा रयेला है, इत्ती गर्मी में नहाता काइकू नहीं? चिरकुट बोला, मुन्ना भाई आप गर्मी की बात कर रयेले हो और ये सटकेला सर्किट देखो ना कब से ठंडा खेल, ठंडा खेल का गाना गा रयेला है। चिरकुट की चिकचिक सुनके सर्किट बोला, अक्खा इंडिया की पब्लिक उसका कॉन्सर्ट का टिकट झपटने की प्लानिंग में लगी है और तेरेकू अभी तक ठंडा खेल, बोले तो कोल्डप्ले समझ में नहीं आया? देख तेरी रिंकी भाभी बोले तो अपनी गर्लफ्रेंड कितनी जिद्दी है वो तो तेरेको मालूमइच है। उसने अपुन को बोला है कोल्डप्ले का टिकट मांगता है तो मांगता है।

सर्किट की ये बात सुनके तो अपुन बोल पड़ा, तेरी छपरी गर्लफ्रेंड को एबीसीडी भी ठीक से नहीं आता, वो कोल्डप्ले में क्या करेगी? उसको रोड साइड में एक अच्छा सा एटीएम देख के उधर छोड़ के आजा, खुश हो जाएगी। एटीएम का एसी मस्त कोल्ड होता है। सर्किट ये सब सुनके थोड़ा हर्ट हो गया पर अपुन से नाराज नहीं हो सकता था, बोला- मुन्ना भाई ये सब अपुन को नहीं मालूम, अपुन कू अभी के अभी कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के टिकट मांगता है। तुमको तो मालूम है ना मुन्ना भाई, अपुन की लाइफ में तुम्हारे बाद कोई सबसे जरूरी इंसान है तो वो रिंकीच है।

AI image

भेजा फ्राई

चिरकुट बोला, भाई देखो इसको मालूम है तुम इसकी सेंटी बातों में अइसे पिघल जाता है जैसे गर्मी में चॉकलेट। चिरकुट की बात सुनके अपुन बोला, सर्किट का अपुन के सिवा हैइच कौन। रिंकी को इस टाइम नाराज नहीं करने का है। ये सुनते ही चिरकुट के भेजे में आ गया कि राजा की इच्छा इच उसका आदेश होता है। वो शाम को पूरे पचास हजार का टिकट लेके आ गया औरबोला लो पचास हजार में खरीद के लाया है अपुन इस टिकट को। पचास हजार???? टिकट तो पांच दस हजार का मिल जाता, अपुन ने चिरकुट से पूछा तो बोला, भाई बस ये मत पूछो। सर्किट ने तुमको सेंटी किया ना। अपुन ने सर्किट की मोटर साइकल बेच डाली और ये कोल्डप्ले का टिकट ब्लैक में लेके आया। ये वोइच धंधा है भाई जो अपुन लोग मूवी हॉल के टिकट के साथ करते थे दस का तीस, दस का तीस। अब इंटरनेट पर ये धंधा अक्खा इंडिया की पब्लिक खुले में कर रयेली है। बस अपुन के जइसा डेढ़ शाणा भी इसके चक्कर में फंस जाएगा ये अपुन ने नहीं सोचा था।

सर्किट को कॉल करके बुला लिया कि कल सुबह आ जाना तेरे वास्ते चिरकुट ने टिकट ले लिया है। अगले दिन चिरकुट को टिकट देने के वास्ते अपुन ने बुलाया तो क्या देखता है, वो एकदम नई दो लाख वाली बाइक में सुनील शेट्टी के माफिक पंट्टी ले रयेला है। ये इतना महंगा ब्रैंड न्यू बाइक किदर से लाया रे चिरकुट। वो बोला भाई कल जो सर्किट की बाइक बेच के टिकट लिया था ना पचास हजार में, आज उसको अपुन ने दो लाख में आगे ब्लैक कर दिया। इसकी रिंकी इस नई बाइक में बैठ के सब भूल जाएगी। सर्किट बोला, और अपुन उसको इसमें बैठा के किदर जाएगा? तो चिरकुट बोला, भाई ये लो डांडिया नाइट के पास। देखादेखी का शोआँफ छोड़ो, कोल्डप्ले का म्यूजिक तो तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा, डिस्को डांडिया में नचाना रिंकी भाभी को। थोड़े दिन के बाद रामलीला का टिकट भी लेके आएगा अपुन तेरे वास्ते।

मुंबइया स्टाइल में मुन्ना और सर्किट का ये भेजा फ्राई आपको कैसा लगा? हमें अपनी राय लिखकर भेजिए इस मेल आईडी पर nbtreader@timesofindia.com और सब्जेक्ट में लिखें-'भेजा फ्राई'

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

ग़रीबी नहीं, ग़रीब से प्रेम की बात करते हैं श्रीकृष्ण

रमेश भाई ओझा

शिकागो की धर्मसभा में स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर जोर दिया था कि स्वस्थ रहो, परिश्रमी बनो और आध्यात्मिक बनो। लेकिन, आज हमारे यहां एक ऐसी विचारधारा पनपी है, जिसमें आध्यात्मिकता को गरीबी और भौतिकता को अमीरी के साथ जोड़ा जा रहा है। आध्यात्मिकता को भौतिकता के आगे छोटा मान लिया गया है, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। असल में आध्यात्मिकता में हिमालय-सी ऊंचाई और समुद्र जितनी गहराई है। भौतिकता में न तो ऊंचाई और न ही गहराई। भौतिकता में केवल शारीरिक सुख के साधन हैं, जबकि आध्यात्मिकता में आनंद ही आनंद। आध्यात्मिकता में त्याग है और भौतिकता में संग्रह प्रवृत्ति को बढ़ावा।

श्रीकृष्ण को किसी भी चित्र, श्रीविग्रह में सादे वस्त्रों में नहीं देखा जाता। हर जगह वह आभूषण, अलंकार पहने हैं। श्रीकृष्ण ने कभी गरीबी से प्रेम की बात नहीं कही, बल्कि गरीबों से प्रेम किया है। जिस राष्ट्र के लोग गरीबी से प्रेम करते हैं, वे न तो खुद और न ही वह राष्ट्र कभी विकास कर सकता है। इंसान गरीबों से प्रेम करे, गरीबी से नहीं। खूब परिश्रम करो, खूब धन कमाओ, पर नीति से। अनीति से कमाया धन कभी चैन से नहीं रहने देगा। जीवन में अगर तरक्की चाहिए तो आशावादी बनना होगा। अपना लक्ष्य स्वयं तय करना होगा और आगे बढ़ना होगा। ऐसा करने पर सफलता निश्चित ही मिलेगी।

भौतिक सुख की चाह में ही लोग उल्टा-सीधा करते हैं। इसके चलते ही भ्रष्टाचार बढ़ा है। लोग रातों-रात धनपति बनना चाहते हैं। कई लोग ऐसा कहते सुन जाते हैं कि हमारे पास बहुत धन है। इसलिए अब सब काम धंधा, सब झंझट छोड़कर ईश्वर भजन में लग जाऊं। काम से निवृत्ति लेकर सिर्फ माला जपने को आप भजन कहते हैं? धर्म के क्षेत्र में यह कैसी गलत विचारधारा पनप रही है! यह जो काम कर रहे हैं आप, वह क्या भजन से कम है। नीति से पैसे कमाना, नीति से व्यवसाय चलाना, यह भी एक प्रकार से ईश्वर की ही पूजा है। एक प्रकार से समाज की सेवा और राष्ट्र के विकास में आपका अमूल्य योगदान है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्रीज से, व्यवसाय, काम-धंधे से कितने लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। भले ही आपको पैसे की कोई जरूरत न हो, लेकिन एक आदमी के पीछे कितने परिवार पल रहे हैं।

जीवन से भागने वालों के लिए सुख नहीं है। इसलिए अपनी विचारधारा को बदलिए। कर्म में प्रवृत्त हों, सुखी बनें, दरिद्रता से मुक्ति पाकर संपन्न बनें और प्रत्येक प्रवृत्ति के केंद्र में प्रभु को देखें, फिर जीवन संगीतमय बन जाएगा। जिस प्रकार से संगीत में एक लय होती है उसी प्रकार से जीवन में लय बनेगी, फिर जीवन को मस्ती में जिएंगे।

इंसान के हृदय में दुखियों के प्रति सहानुभूति हो। हम उनके दुखों को बांटें, कम करें। इससे जो संतुष्टि मिलती है, उससे भी जीवन संगीतमय बनता है। समझने की बात है कि यह संसार विशाल परिवार है। सुखी बनें और दुखियों को भी सुखी बनाएं, यह अध्यात्म के मार्ग पर चलकर संभव है।

प्रस्तुति : सुभाष चन्द्र शर्मा

कोर्ट तो आख़िरी रास्ता होता है, कई ग़ैर-ज़रूरी मामले जूडिशरी तक जा रहे

विशुद्ध राजनीति

इंटरव्यू

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, चार बार के राज्यसभा सांसद **अभिषेक मनु सिंघवी** इन दिनों अपनी पैरवियों को लेकर लगातार सुर्ख़ियों में हैं। देश की मौजूदा सियासत, जूडिशरी के सामने आने वाले मामलों और इसरे अहम मुद्दों को लेकर मंजरी चतुर्वेदी ने उनसे बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश :

■ आज तमाम ऐसे मामले हैं, खासकर विपक्षी दलों की सरकारों या उनके नेताओं से जुड़े, जो कोर्ट पहुंच रहे हैं। आप उनमें से कई में सीधे तौर पर जुड़े हैं...

मैं इसे सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों नजरिए से देखता हूं। सकारात्मक इसलिए कि फिलहाल देश में एक ही अंग (न्यायपालिका) बचा है, जिससे न्याय की अपेक्षा और भरोसा है, और वह मिलता भी है। नकारात्मक इसलिए क्योंकि सुशासन में यह नहीं होना चाहिए कि आपको किसी दूसरे अंग के पास बार-बार जाने की जरूरत पड़े। न्यायपालिका के पास तब जाते हैं, जब कोई विकल्प नहीं बचता। आज जूडिशरी के सामने ऐसे कई मामले जा रहे, जिन्हें वहां पहुंचना ही नहीं चाहिए।

■ आपने अभी जूडिशरी पर विश्वास की बात कही। हाल ही में एक मौके पर प्रधानमंत्री देश के चीफ जस्टिस के घर गए थे। इसे लेकर काफी चर्चा भी हुई थी।

यह निर्णय जिधर का भी रहा हो, चाहे न्यायपालिका का या फिर कार्यपालिका का, इससे बिल्कुल बचा जा सकता था। अगर इसमें कोई उद्देश्य या द्वेष न भी माने, तो भी बेहतर होता कि यह घटनाक्रम होता ही नहीं।

■ इस बार आपके लिए राज्यसभा में जाना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, खासकर हिमाचल प्रदेश में जो हुआ, उसके बाद?

मैंने हिमाचल में मानवीय मूल्यों का शीर्ष देखा और साथ ही नकारात्मकता का घृणात्मक रूप भी। भारत के इतिहास में पहली बार राज्यसभा चुनाव में टाई हुआ। टाईबेकर में ऐसा विचित्र नियम लागू किया गया, जहां बक्से से जिसका नाम निकलता है, वह हारता है। जिस दिन यह अजीबोगरीब नतीजा निकला, उसी दिन पार्टी ने दागियों को निष्कासित कर दिया। इसे आप प्राकृतिक न्याय कहिए या दैविक, उन 9 दागियों में से 6 चुनाव हार गए। मुद्दा मेरा राज्यसभा जाना नहीं, मुद्दा यह है कि ऐसी घटनाएं जनता के बीच हम सब का कद छोटा और छवि धूमिल करती हैं।

■ क्या 'एक देश एक चुनाव' का बिल संसद और अदालत से पास होगा?

यह अपने आप में कई सवालों को समेटे हुए है। सवाल है कि तीन से पांच संवैधानिक संशोधन उस स्थिति में कहां से आएंगे, जब आप 80 सीटें हार चुके हैं। अगर किसी जादुई छड़ी से यह परित भी हो गया, जो फिलहाल असंभव दिखता है, तो सवाल है कि क्या आप कानून द्वारा लोकतंत्र के जनादेश को नकार सकते हैं? यह कवायद देश की ऊर्जा और समय की खराबी है, क्योंकि आपके पास इतनी क्षमता नहीं कि इस पर आप सम्मति बना सकें।

■ संसद के इसी कार्यकाल में लोकसभा का परिसीमन भी होना है। दक्षिण के राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। कानूनी रूप से मसले को कैसे देखते हैं?

परिसीमन अपने आप में एक जटिल समस्या है, लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है। इस पर कई चीजें निर्भर हैं, मसलन- महिला आरक्षण बिल इसी के बाद जमीन पर उतर पाएगा। इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो राज्य अपनी आबादी को नियंत्रित करते हैं, उन पर किसी तरह का कोई दंड न लगे। इसका एक यही हल हो सकता है कि आर्थिक फायदों द्वारा ऐसे प्रदेशों को कंपनसेट किया जाए।

■ BJP और सरकार, राहुल गांधी की मंशा पर लगातार सवाल उठा रही है...

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि आप आलोचना कर सके, सुझाव दे सकें। अगर इतनी-सी बात नहीं समझ सकते, तो यह दयनीय है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को राजनीतिक द्वेष के चलते निशाना बनाया जा रहा है। यह सरकार की उस घबराहट और बौखलाहट को दर्शाता है, जो उसे देश की जनता द्वारा पूछे जा रहे सवालों के चलते हो रही है, जिसका जवाब उसके पास नहीं है।

■ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर राय क्या है?

वक्फ के मुद्दे पर सरकार के दो ही काले उद्देश्य हैं- इस मामले में सरकार को कंट्रोलिंग सीट पर डालना और जिनके लिए यह कानून बना था, जो वक्फ द्वारा दान देते हैं या समाज कल्याण करते हैं, उनकी स्वायत्तता को खत्म करना। यह बिल JPC को इसलिए भेजा गया, क्योंकि विपक्ष ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ अमेरिका से रिश्ते

23 सितंबर का संपादकीय 'बेहतरी की ओर' पढ़ा। इससे साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का पीएम नरेंद्र मोदी को अपने निजी आवास पर बुलाना इस बात का संकेत है कि इन दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत तालमेल के साथ-साथ दोनों देशों के रिश्ते आज की तारीख में कितने बेहतर हो चुके हैं। साल 2006 में परमाणु ऊर्जा समझौते के बाद से ही भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं, फिर सरकार चाहे किसी की भी रही हो। वैसे भी, अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ पीएम मोदी का तालमेल अच्छा रहा है। चुनावी माहौल में अमेरिका के नागरिकों और वोटरों में पीएम मोदी को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है।

राजेश जैन, दिल्ली

■ सचाई की कीमत

यह पत्र 10 सितंबर को 'भेजा फ्राई' कॉलम में प्रकाशित लेख 'पंकिट खाली भेजा फ्राई पर अपुन हाई फाई बन जाएगा' से संबंधित है। लेख में सर्किट की बेवकूफी और उसके दोस्तों के संवाद आजकल की सोच को उजागर करते हैं। बिलकुल सही बात है कि अब दिखावे पर खूब जोर रहता है। झूठे दिखावे से थोड़ी देर के लिए सम्मान मिल सकता है, लेकिन पोल खुल ही जाती है।

प्रमोद रावत, ईमेल से

■ तालमेल जरूरी

हाल में जिस तरह से रेल हादसे बढ़े हैं और साजिश का एंगल सामने आ रहा, उससे लगता है कि कहीं न कहीं सुरक्षा तंत्र कमजोर हुआ है। कानपुर और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर की घटना गंभीर स्थिति को दर्शाती है। दोनों ही मामलों में ड्राइवर की सूझबूझ काम आई। हालांकि हमारे देश का रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, और इसकी निगरानी करना, इसे सुरक्षित रखना चुनौतीपूर्ण है। कई बार स्थानीय प्रशासन और रेलवे सुरक्षा बल के बीच तालमेल की कमी भी देखने को मिलती है।

कपिल राणा, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

बाइडन को गिफ्ट में पीएम मोदी ने दी चांदी की 'ट्रेन' - एक खबर

- क्या मेक इन इंडिया का यह नया संस्करण है।

स्वाति त्रिपाठी

डॉ. टी. आई. पी. 21/2/2/2 मध्यमिकाएं पुस्तिका / लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्मुद्रण मुद्रण, प्रतिलिपि / सर्वाधिकारी सेवित, प्रोप्रीटर एवम कर्मचारी विनियोग के लिए संपादक बाबत मुद्रित / मालिकाना स्वामित्व, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, मुम्बई** द्वारा, **प्रोप्रीटर ऐंड पब्लिशर्स** और चीफ एडिटर, टी.एन. चेतन, 10 टी. ग्रेहाम रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, प्रिंटिंगप्रेस, राजघाट, दिल्ली से मुद्रित। **फोन:** 26383333, 26383334, 26383335 ; **फैक्स:** 26383336 ; **वेबसाइट:** www.nbt.nic.in ; **ई-मेल:** nbtedit@timesofindia.com ; **टेलिग्राम:** नवभारत, दिल्ली ; **टेलेक्स:** 31-61-2 ; **टेलिफोन:** 26383333 ; **फैक्स:** 26383336 ; **वेबसाइट:** www.edit.nbt.in ; **संपादक:** (हिन्दी संस्करण) ; **अनुवाद संपादक:** (हिन्दी संस्करण) ; **कार्यकारी संपादक:** (हिन्दी संस्करण) ; **कार्यकारी संपादक:** (हिन्दी संस्करण) ; **कार्यकारी संपादक:** (हिन्दी संस्करण) ; **कार्यकारी संपादक:** (हिन्दी संस्करण) ; **कार्यकारी संपादक:** (हिन्दी संस्करण) ; **कार्यकारी संपादक:** (हिन्दी संस्करण) ; **कार्यकारी संपादक:** (हिन्दी संस्करण) ; **कार्यकारी संपादक:** (हिन्दी संस्करण) ; **कार्यकारी संपादक:** (हिन्दी संस्करण) ; **कार्यकारी संपादक:** (हिन्दी संस्करण) ; **कार्यकारी संपादक:** (हिन्दी

4.2 प्रतिशत थी बेरोजगारी की दर इस वर्ष अगस्त में अमेरिका में, जबकि एक वर्ष पहले यह 3.8 प्रतिशत थी। वस्तुतः बेरोजगारी दर को कम करने के लिए अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की गई है।

आजकल

ब्याज दरों में कटौती का आर्थिकी पर असर

राहुल लाल
आर्थिक मामलों के जानकार

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व (फेड) ने हाल ही में ब्याज दरों में 50 आधार अंक की कटौती की है। फेड ने 14 माह तक ब्याज दरों को 23 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रखा था, परंतु अब ब्याज दरों में कटौती का नया चक्र प्रारंभ होगया है। यह एक तरफ अमेरिका में आर्थिक मंदी का संकेतहै, तो वहीं दूसरी ओर इससे भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए विदेशी पूंजी निवेश की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। इससे डालर की तुलना में रुपया भी मजबूत होगा, जो भारत जैसे आयातोन्मुखी देश के लिए वरदान साबित होगा। साथ ही, कच्चे तेल पर भी इसका असर दिखेगा

पूंजि डालर मे भारत को बड़ी संख्या मे व्यापारिक भुगतान करना होता है, लिहाज इसके कमजोर होने से हमे लाभ होगा। फाइल

अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने बेंचमार्क ब्याज दरों को 5.25-5.50 प्रतिशत से 50 आधार अंकों की कटौती करके 4.75-5.0 प्रतिशत कर दिया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को 2022 के आरंभ से अब तक 11 बार बढ़ाया था, यही कारण है कि ब्याज दर 23 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। अमेरिकी सरकार ने कोविड महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर सहायता कार्यक्रम शुरू करके अर्थव्यवस्था में लगभग पांच लाख करोड़ डालर डाले थे। इस अतिरिक्त नकदी के साथ लोगों और कारोबारियों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा था, जिससे मांग आसमान छू गई। यही कारण था कि जून 2022 में अमेरिका में मुद्रास्फीति 9.1 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो 40 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर था। ऐसे में अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को बढ़ाने का चक्र 2022 से प्रारंभ किया था, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। ब्याज दरों को बढ़ाने से उधार लेना महंगा हो जाता है, फलतः कंपनियां और लोग खर्च कम करते हैं। इससे मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलती है।

लेकिन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के फेडरल रिजर्व के इन प्रयासों से बेरोजगारी की समस्या उभरने लगी। उच्च ब्याज दरों का मतलब यह भी है कि कंपनियों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, जिससे लागत में कटौती, धीमी गति से विस्तार एवं छंटनी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इससे बेरोजगारी दर में वृद्धि होने लगी। इसलिए पिछले साल फेडरल रिजर्व ने दरों को बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। फेड ने बेरोजगारी दर को कम करने के लिए ब्याज दरों में कटौती की, जबकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पहले ब्याज दरों में वृद्धि की थी। अमेरिका में 4.2 प्रतिशत की बेरोजगारी दर यद्यपि ज्यादा नहीं है, लेकिन बेरोजगारी का लगातार इस प्रकार बढ़ना मूलतः आर्थिक मंदी को भी प्रतिबिंबित करता है। अमेरिकी फेडरल बैंक ब्याज दरों में यदि केवल 25 आधार अंकों की कटौती करती तो कहा जाता कि इससे मुद्रास्फीति के बहुत बुरे दौर की वापसी को रोका जा रहा है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संदर्भ होता। लेकिन फेड ने जिस तरह ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की, उसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी के और बढ़ने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है।

भविष्य के कदमों की रूपरेखा : फेड ने 50 आधार अंकों की कटौती के साथ सहजता की शुरुआत की है, लेकिन अभी से इसके भविष्य के कदम और दरों में कमी की संभावनाओं पर भी चर्चा प्रारंभ हो गई है। फेड अधिकारियों के अनुमान बताते हैं कि इस वर्ष दरों में एक और 50 आधार अंकों की कमी हो सकती है, जबकि 2025 में एक प्रतिशत की कमी की जा सकती है। इस संदर्भ में यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सहजता का यह चक्र आम चक्रों से अलग है। कम ब्याज दरों के कारण व्यय में अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि हो सकती है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों से जुड़ी निर्णय को ''नीतिगत दरों को निरपेक्ष दरों के करीब ले जाने का'' एक व्यवस्थित कदम बताया। वस्तुतः निरपेक्ष दर ऐसी नीतिगत ब्याज दर है, जो न तो प्रतिबंधात्मक हो और न ही समायोजन वाली। महामारी के पहले माना जा रहा था कि 2.5 प्रतिशत की दर निरपेक्ष दर होगी, लेकिन उसके बाद से इसमें वृद्धि हुई है। एक अनुमान के अनुसार, यह 3.5 से 4.8 प्रतिशत के बीच है। इससे ब्याज दरों में कमी की गुंजाइश सीमित हो जाती है।

भारत पर प्रभाव : हाल ही में बैंक आफ इंग्लैंड और यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी ब्याज दरों में कमी की है। वैश्विक वित्तीय बाजार और पूंजी प्रवाह अमेरिकी फेडरल बैंक के कदमों से अधिक प्रभावी होते हैं। वित्तीय हालात को सहज बनाने के लिए यूएस फेड से ब्याज दरों में कमी की अपेक्षा थी। बहरहाल, इस बार यूएस फेड की दरों में कमी का चक्र कई मायने में अलग होगा, क्योंकि ब्याज दर कम होने पर भी शून्य स्तर से काफी अधिक स्तर पर होगी। ज्ञात हो कि वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान फेड ब्याज दर काफी समय तक शून्य के इर्द गिर्द रही है। वैश्विक पूंजी प्रवाह भी अमेरिका में तुलनात्मक रूप से कम रह सकता है, क्योंकि अमेरिकी सरकार को घाटे की भरपाई की जरूरत है।

भारत में निवेश की संभावना : अमेरिका में कम ब्याज दरें भारत जैसे देशों में निवेश को अधिक आकर्षक बना सकती हैं। कैरी ट्रेड की स्थिति इसमें मददगार है। यह रणनीति, जिसे कैरी ट्रेड के रूप में जाना जाता है, उसके तहत निवेशक जहां अमेरिका में पैसे उधार लेते हैं (दरें कम होने के कारण) और इसे वहां निवेश करते हैं, जहां दरें अधिक है। इससे भारत जैसे बाजारों में अधिक पूंजी प्रवाहित हो सकती है, जिससे संभावित रूप से शेयर बाजारों को बढ़ावा मिल सकता है। यही कारण है कि पिछले सप्ताह सेंसेक्स ने रिकार्ड 84 हजार का आंकड़ा पार किया, जबकि निफ्टी भी 25 हजार से ऊपर रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों के नजरिए से देखें तो वे बाजारों में खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वे भारत व अन्य देशों में निवेश कर सकें। अन्य उभरते बाजार कमजोर डालर और दर कटौती के लिहाज से भारत के मुकाबले अधिक संवेदनशील हैं। हालांकि भारत को उभरते बाजारों में ब्राजील से कड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि वहां ब्याज दरें ऊंची हैं। वहीं दक्षिण एशियाई देश भारत के मुकाबले कमजोर डालर के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील हैं। भारत समेत एशियाई देश पहले ही ब्याज दरों में कटौती कर सकते थे, लेकिन आरबीआइ समेत अधिकांश ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की, क्योंकि वे अपनी मुद्रा को कमजोर नहीं होने देन चाहते थे।

निष्कर्ष : भारत फेड के सख्ती के तूफान से अपेक्षाकृत सहजता से निपटने में कामयाब रहा है, क्योंकि हमारे यहां विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति मजबूत थी। फेड के सहजता चक्र के बीच भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूंजी का प्रवाह रुपये पर अनावश्यक रूप से ऊपरी दबाव न बनाए। यदि ऐसा हुआ तो भारत के कारोबारी क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर असर होगा। नीतिगत संदर्भ में आरबीआइ से अपेक्षा होगी कि वह मुद्रास्फीति की दर को टिकाऊ स्तर पर चार प्रतिशत की मुद्रास्फीति की दर से सुसंगत बनाएं। आरबीआइ ने मुद्रास्फीति को कम रखने के लिए फरवरी 2023 से रेपो दर को 6.5 पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआइ मौद्रिक समिति की अगली बैठक 7-9 अक्टूबर को होने वाली है। अब भारत में सबकी नजरें आरबीआइ की इस बैठक पर है, जहां फेड रेट कटौती पर उसकी प्रतिक्रिया सामने दिखेगी। ऐतिहासिक रूप से भारतीय रेपो रेट अमेरिकी ब्याज दरों से भी प्रभावित रही है। हालांकि आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहले ही संकेत दिया है कि भारत को इसका अनुसरण करने और अपनी दरों को कम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यूएस फेड ने श्रम बाजार की कमजोरी के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई है। फेड ने बाजार की बदलती उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए 50 आधार अंक की बड़ी कटौती के साथ ब्याज दर कटौती चक्र शुरू किया है। मुद्रास्फीति अस्थाई है और दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी। फेड ने बाजार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबा सफर तय किया है। एक तरफ यह अमेरिका में आर्थिक मंदी का संकेतक है, तो वहीं दूसरी ओर यह ब्याज दर कटौती कमजोर डालर कम दरों के साथ उभरते बाजार में पूंजी प्रवाह को बढ़ाएगी।

डालर की तुलना में मजबूत हो सकता है रुपया

अमेरिका में ब्याज दरों में बार बार कमी आने से भारतीय रुपये जैसी अन्य मुद्राओं के साथ डालर की विनिमय दर में भी कुछ कमी आएगी। दूसरे शब्दों में, डालर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर मजबूत हो सकती है। जैसे-जैसे विदेशी निवेशक इनवेस्टमेंट के उद्देश्य से अपनी करेंसी को भारतीय रुपये में बदलेंगे, रुपये की मांग बढ़ेगी। इससे काफी हद तक संभव है कि डालर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा। बाजार में यह नजर भी आया। फेड ब्याज दर में कमी के बाद रुपया मजबूत होकर 83.48 डालर पहुंच गया। मजबूत रुपया आयात की लागत को कम कर देता है। वहीं वह विदेशी खरीदारों के लिए उनके सामान को अधिक महंगा बनाकर भारतीय निर्यातकों को भी दुष्प्रभावित करता है। भारतीय आर्थिकी आयातोन्मुखी बनी हुई है, इसलिए मजबूत रुपया हमारे लिए लाभप्रद है।

डालर में ऋण चुकाना सस्ता होगा : अमेरिकी ब्याज दर में कटौती से भारतीय कंपनियों के लिए डालर में किए गए ऋण की चुकान भी सस्ता हो जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कम ब्याज दर से ऋण ब्याज की अदायगी लागत कम हो जाती है। इसके अलावा, कमजोर डालर का मतलब यह भी है कि आपको उसी राशि के ऋण निपटान करने के लिए कम रुपये की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि आज एक डालर की कीमत 85 रुपया है। यदि ब्याज दर में कटौती से डालर कमजोर होकर 84 रुपया हो जाता है, तो 10 करोड़ डालर का ऋण चुकाना सस्ता हो जाता है यानी 850 करोड़ से रकम 840 करोड़ रुपये आ जाती है।

फेड ने निवेशकों की मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर आश्वस्त किया है, लेकिन विश्लेषक 50 आधार अंकों की कटौती को मंदी से लड़ने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक का पहला कदम मान रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी दुनिया में तेल की मांग स्थिर हो सकती है। चीन में तेल के बढ़ते उत्पादन के बीच पेट्रो देश अपनी कटौती को धीरे-धीरे कम सकते हैं, क्योंकि वहां भी बाजार हिस्सेदारी को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी हुई है। भू-राजनीतिक कारणों से कीमतों में बढ़ोतरी अल्पावधि के लिए हो होती है। जब तक भू-राजनीतिक हालात ज्यादा खराब न हो, तब तक तेल की कीमतों में गिरावट का मौजूदा रुख थोड़ा और लंबा चल सकता है।

(राहुल लाल)

खरी-खरी

वाइफ का हार

अलंकार रस्तोगी

हाल ही में उन्होंने ढाई लाख रुपये की एक नई बाइक खरीदी है। बाइक पर बैठने से भी ज्यादा उन्हें प्रेशर वाला हार बजाने में आनंद की अनुभूति होती है। हार्न बजाते ही उनके अंदर किसी दिव्य पुरुष की आत्मा के वास का आभास होने की तरह प्रतीत होता है। हार्न बजाते ही वह किसी स्वयंभू सम्राट की तरह बर्ताव करने लग जाते हैं। वह अपने हार्न की आवाज से अपनी उस दमित इच्छा की पूर्ति करते हैं जो वह चक्रवर्ती सम्राट न बन पाने के कारण नहीं कर पाए थे। वह हार्न से ही लोगों को पटकनी देने और धूल चटा देने का वर्चस्व भरने लगे हैं।

हार्न बजाना अब उनके मौलिक अधिकार की तरह बन चुका है। उनकी सुबह हार्न के बंदन से, सांझ हार्न के कीर्तन से और रात हार्न के क्रंदन से गुंजायमान रहती है। हार्न उनके जीवन का अभिन्न अंग सा बन गया है। उनका व्यक्तित्व अब हार्न ही है। ऐसा लग रहा है मानो वह उसमें कोई विशिष्ट शोधकार्य कर रहे हों व फिर उसके अध्येता बनना चाह रहे हों। उनका स्वयं का कुछ भी नहीं है। उनका हर अर्जित और परमार्जित बस हार्न से ही है। लड़कियों के कालेज जैसे स्थान विशेष पर हार्न को बजाना वह किसी क्रांतिकारी आंदोलन से कम नहीं मानते हैं। उनके इस साहसिक कार्य के लिए वह अपनी मित्र मंडली द्वारा 'मजनू श्री' की उपाधि से भी अलंकृत किए जा चुके हैं।

ट्रैफिक जाम और जन्नत उनके लिए एक समान ही है। जहां गाड़ियों के लिए हिलने की भी जगह संभव नहीं हो, वहीं भी जनाब के हार्न का 'नान स्टाप' संगीत जारी रहता है। यह संगीत का 'कंसर्ट' तब तक जारी रहता है, जब तक अगल-बगल के लोग बहरे होने की कगार पर आकर रहम की भीख न मांगने लग जाएं या फिर कोई उनके पास आकर उनके इस पुनीत कार्य के लिए उनकी माता और बहन का स्तुति वंदन न करने लग जाए। हार्न में ही उनकी आत्मा है। हार्न ही उनका परमात्मा है। हार्न ही उनकी कुंठा निकालने का तरीका है। हार्न ही उनकी ईर्ष्या प्रदर्शन का मंच है। हार्न ही सबकुछ है उनके लिए, परंतु दुर्भाग्यवश हार्न मोह के कारण वह स्वयं नहीं बचे हैं एक सभ्य समाज के लिए।

X पोस्ट

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सीएम की कुर्सी पर न बैठकर उसे खाली रखना असल में उस संविधान का अपमान है, जिसकी शपथ ली गई! यह मानसिक दासता का एक नायाब नमूना है।
त्रिभुवन@tribhuvun

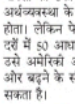
लोगों ने उस अरविंद केजरीवाल पर अपना दुलार बरसाया था, जो एक साधारण से मकान में रहता था, न कि आलीशान महल में रहने वाले शख्स पर। अभी भी उन्होंने बहुत कुछ नहीं गंवाया है, लेकिन उन्हें वहीं से आरंभ करना होगा, जहां से पार्टी शुरू हुई थी। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं।
आशुतोष@ashutosh83B

कुमारी सैलजा खुद सामने आकर क्यों नहीं कह देतीं कि पूरी कांग्रेस हरियाणा में एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। न किसी को कोई सफाई देने की जरूरत पड़ेगी, न कोई फोटो जारी करने की जरूरत होगी।
अरविंद चोटिया@arvindchotia

मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड का सफाया करने के लिए सात साल में करीब 500 एनकाउंटर किए। तब न तो मीडिया और न ही नेताओं ने मारे गए अपराधियों की जाति पर कोई प्रश्न किया। यूपी में अपराधियों को लेकर गजब का जातिवाद दिख रहा है।
उज्ज्वल शाह@UJJAVALSHAH2

जागरण जनमत — कल का परिणाम

भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने में सफल रहेगी?

सभी 6,000 से अधिक मतों में

आज का सवाल
क्या श्रीलंका में दिसानायके का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए चिंता का विषय है?

परिणाम जानने इंटरनेट संस्करण के चौथे को मत दें।

जनपथ

दिल्ली में भी ले लिये आज भरत अवतार,
कुर्सी बाजू में धरे चल निकली सरकार।
चल निकली सरकार अजब कलियुग की श्रद्धा,
पूजा उसकी हेय जमाना पर जी बैठा।
यह नौटंकी देख देख मैं उड़ती खिल्ली,
काश! समझती खेल बुद्धिमानी की दिल्ली!
- ओमप्रकाश तिवारी

बंगाल डायरी

...और 17 वर्ष बाद 17 को दोहराया इतिहास

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

इतिहास स्वयं को दोहराता है। यह उक्ति एक बार फिर बंगाल में प्रमाणित हुई है, क्योंकि 17 वर्ष पहले और 17 तारीख को ही हुई घटना इस तरह से एक बार फिर लोगों के सामने आएगी, यह शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इसी 17 सितंबर को कोलकाता में ऐसा कुछ देखने को मिला, मानो 17 वर्ष पहले हुई घटना की पुनरावृत्ति हो। फर्क केवल इतना था कि 17 वर्ष पहले पद से हटने और हटाने वाले नाम व चेहरे अलग थे, परंतु दोनों ही मामले में सबसे बड़ी समानता यह है कि पद से हटाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी और हटने वाले अधिकारी कोलकाता पुलिस के आयुक्त थे।

इस प्रकरण की शुरुआत 17 वर्ष पहले 2007 में हुई थी। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे और कोलकाता पुलिस के आयुक्त प्रसून मुखर्जी थे। विपक्ष की नेता ममता बनर्जी थीं। कोलकाता के एक प्रसिद्ध उद्योगपति की बेटी को रिजवानुर रहमान नामक ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाने वाले शिक्षक से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी भी कर ली। उसी वर्ष 21 सितंबर को रिजवानुर रहमान की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। यह विषय मुद्दा इसलिए बन गया, क्योंकि तत्कालीन पुलिस आयुक्त प्रसून मुखर्जी, कोलकाता पुलिस के उपायुक्त अजय कुमार और ज्ञानवंत सिंह पर उद्योगपति को मदद करने और रिजवानुर को धमकी देने के आरोप लगे थे। हाई कोर्ट के निर्देश पर हत्याकांड की सीबीआइ जांच का आदेश दिया गया था। इसे लेकर खूब आंदोलन हुए थे। ममता ने इस मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन शुरू किया और पुलिस आयुक्त अन्य आरोपित पुलिस अधिकारियों को हटाने की मांग की थी। इसके बाद 17 अक्टूबर को दुर्गापूजा की महाषष्ठमी के दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने आयुक्त के पद से प्रसून मुखर्जी और दोनों उपायुक्तों को हटाने की घोषणा की थी।

बुद्धदेव भट्टाचार्य। फाइल

ममता बनर्जी। फाइल

अब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्याकांड में पुलिस की भूमिका पर प्रश्न उठ चुके हैं। इस मामले में कोलकाता के टाला थाने के तत्कालीन थानेदार की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आम लोगों से लेकर जूनियर डाक्टरों के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 17 सितंबर की मध्य रात्रि को कोलकाता पुलिस आयुक्त के पद से विनीत गोयल, पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता समेत स्वास्थ्य विभाग के दो और अधिकारियों को हटाने की घोषणा करनी पड़ी। इसके बाद मनोज वर्मा आयुक्त बन गए। इसमें अंतर केवल इतना था कि 2007 में तारीख 17 अक्टूबर थी और 2024 में 17 सितंबर।

इस प्रकरण में एक और खास बात हुई, जो नेताओं के लिए किसी सीख से कम नहीं है। नेता जब विपक्ष में होते हैं तो सरकार और सत्तारूढ़ दलों को घेरने के लिए बिना सोचे-समझे कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, परंतु समय हर दिन समान नहीं रहता और जब समय बदलता है तो ऐसे बयान देने वाले नेताओं को बगल झांकने को मजबूर होना पड़ता है इसीलिए तो सदियों पहले कबीर दास जी ने लिखा था- 'बोली एक अनमोल है, जो कोई बोलै जानि, हिये तराजू तौलि के, तब मुख बाहर आनि।' परंतु लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, इसीलिए कुछ भी बोल देते हैं और भूल जाते हैं कि उनकी कही बातें किसे दिन उनके ही गले की हड्डी बन सकती है। ऐसा ही कुछ ममता बनर्जी के साथ हुआ। 17 वर्ष पहले उन्होंने जो बयान दिया था, उसी ने उनको मजबूर कर दिया।

दरअसल, आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या के बाद से ही जूनियर डाक्टर कोलकाता पुलिस आयुक्त के पद से विनीत गोयल को हटाने की मांग कर रहे थे। पिछले सप्ताह सीमावर्ती की जब ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर जूनियर डाक्टरों के साथ बैठक हो रही थी तो उस दौरान गोयल को हटाने की मांग उठी तो उस पर काफी देर तक गतिरोध बना रहा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कह रही थीं कि दुर्गापूजा तक गोयल को हटाना सही नहीं होगा। इस पर जूनियर डाक्टरों ने 2007 में रिजवानुर रहमान कांड को लेकर दिए उनके बयान का हवाला दे दिया। उस समय विपक्ष की नेता ममता ने संबद्धता सम्मेलन में प्रश्न उठाया था कि आरोपित पुलिस अधिकारियों को उनके पद पर रखकर न्याय कैसे संभव होगा? उस समय तो दुर्गापूजा शुरू हो चुकी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री भट्टाचार्य ने आयुक्त के साथ ही दो उपायुक्तों को भी हटाया था। जैसे ही यह बात जूनियर डाक्टरों ने कही तो विनीत गोयल को हटाने पर ममता सहमत हो गईं, हालांकि इस बैठक से कुछ दिन पहले ममता ने मीडिया से कहा था कि वह विनीत को अभी नहीं हटा सकतीं। गोयल ने स्वयं भी इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी, लेकिन अगले दुर्गापूजा है, कानून और व्यवस्था देखने वाले लोगों की जरूरत है, परंतु सुश्री बनर्जी के लिए 17 वर्ष पहले दिए उनके बयान ने ही उनके लिए असहज स्थिति पैदा कर दी।

मंथन

यमुना के अस्तित्व की चिंता

ज्ञानेंद्र रावत
वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद

दिल्ली व हरियाणा में यमुना का एक बड़ा हिस्सा प्रवाहमान है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कुछ माह बाद दिल्ली में भी होंगे, परंतु यमुना के अस्तित्व की चिंता किसी दल को नहीं है

दिल्ली के साथ यमुना की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान जुड़ी हुई है। यह नदी इस शहर के लिए जीवन दायिनी रही है। परंतु विडंबना यह कि देश के राजधानी की एक बड़ी जनसंख्या को जल उपलब्ध कराने वाली इस नदी की चिंता किसी को नहीं है। न दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार को और न केंद्र की भाजपा सरकार को। आजकल दिल्ली व केंद्र में सत्तासीन दोनों दलों के साथ कांग्रेस को हरियाणा चुनाव में सत्ता कैसे मिले, इसकी चिंता सताए जा रही है और इस हेतु हरसंभव जोड़-तोड़ में भी वे लगी हैं। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में यमुना नदी का बहाव क्षेत्र लगभग तीन सौ किलोमीटर तक विस्तृत है। लिहाजा यह नदी इस राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

दुखद बात यह है कि किसी भी दल ने यमुना के प्रदूषण के बाबत चुनाव में आज तक एक भी शब्द नहीं बोला है। यह राजनीतिक दलों की यमुना के प्रति संवेदनहीनता का जीता जागता संबूत है। भले दिल्ली-हरियाणा की जीवनदायिनी यमुना मर रही हो, वह जहरीली हो गई हो, उसमें लेड, कापर, जिंक, निकेल, कैडमियम और क्रोमियम जैसे सेहत के लिए हानिकारक तत्व मौजूद हों और तो और यमुना में रसायन के चलते बजबजाते झाग को रोकने के लिए समूचे सीवेज के ट्रीटमेंट की जरूरत हो, लेकिन उसकी चिंता इस चुनाव में किसी को नहीं है।

वैसे यमुना की बदहाली से ये दोनों राज्य सरकारें भलीभांति परिचित हैं। बीते दशकों का इतिहास इसका गवाह है कि यमुना साल-दर-साल कितनी प्रदूषित हुई है। लोकसभा की स्थायी समिति द्वारा यमुना के संदर्भ में तैयार रिपोर्ट में यह राजफाश किया गया है कि यमुना के जल में भारी धातु के प्रदूषक तत्वों की भरमार है जो जानलेवा बीमारियों के कारण हैं। समिति ने यमुना में पाए जाने वाले बीओडी, सीओडी और फीकल कोलीफार्म जैसे प्रदूषक तत्वों की सूची तैयार की है। साथ ही, नदी में पाए जाने वाले सेहत के लिए जानलेवा बन रहे छह धातुओं यथा लेड, कापर, जिंक, निकेल, कैडमियम और क्रोमियम से होने वाले नुकसान की सूची भी तैयार की है। समिति ने माना है कि लेड से बच्चस्कों में रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी नसों से संबंधित पैरीफेरल न्यूरोपैथी और खासकर बच्चों में काम्प्रिटेव इंपेयरमेंट, कापर से सिर दर्द, किडनी संबंधी बीमारी, उल्टियां और दस्त के साथ नीसिया, जिंक से लिवर व किडनी से जुड़ी बीमारियों के साथ उल्टी-दस्त होने, निकेल से न्यूरोटाक्सिक, जेनेटाक्सिक और कार्सीनोजेनिक, कैडमियम से किडनी और लिवर से जुड़ी बीमारी के साथ गैस्ट्रो व ओव्हरोथ और क्रोमियम से न्यूरोनल डैमेज, हेपेटिक व गैस्ट्रो इंटैस्टाइनल जानलेवा बीमारियां जन्म लेती हैं। समिति ने यमुना में झाग बनने से रोकने हेतु दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्रकाहित होने वाले समूचे सीवेज का ट्रीटमेंट किए जाने की जरूरत बताई है। समिति ने जल संसाधन विभाग को सुझाव दिया है कि वह यमुना नदी के लिए भी स्वच्छ गंगा मिशन की तर्ज पर एक कोष की स्थापना करे, ताकि पैसे की कमी आड़े न आए।

वैसे यमुना की सफाई पर बीते ढाई दशकों में अभी तक करोड़ों रुपये स्वाहा हो चुके हैं। उसके बाद भी यमुना में अमोनिया के बढ़ते स्तर पर अंकुश नहीं लग सका है। पिछले लगभग एक दशक तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने बरसों पहले यह दावा किया था कि यमुना को वे पूरी तरह से स्वच्छ करवाएंगे। उन्होंने तो यह भी कहा था कि वह स्वयं यमुना में स्नान भी करेंगे। परंतु अब तक तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है।

व्यापक प्रयासों से ही यमुना नदी को स्वच्छ एवं निर्मल बनाया जा सकता है। फाइल

आज यदि कालिंदी कुंज के पास यमुना को देखें तो वास्तव में ऐसा लगता है जैसे किसी नदी के आसपास बर्फ की चादर बिछी हो। उसके आसपास का किनारा सफेद झागों से पटा हुआ नजर आता है। वस्तुतः यमुना को प्रदूषण मुक्त किए जाने की दिशा में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता में बढ़ोतरी किए जाने, नालों के पानी को सीधे नदी में गिरने से रोकने, शहरी और जेजे कलस्टर में सीवर नेटवर्क निर्माण, शोधित पानी के दोबारा उपयोग, यमुना कछार में चलने वाली और जिलों से गाद निकालने से जुड़ी परियोजनाओं में हीला-हवाली कहें या नाकामी पूरी तरह जिम्मेदार है। इसका पर्यवसान दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की एक हालिया रिपोर्ट में हुआ है। ऐसे में यमुना का नाले के रूप में बहना उसकी नियति बन चुकी है। हरिद्वार और वाराणसी की तर्ज पर उसके घाटों का सौंदर्यीकरण कर पर्यटक स्थल बना और वहां आरती का कार्यक्रम आयोजित करने से यमुना की बदहाली छिप जाएगी, यह जनता को धोखे में रखने के सिवाय कुछ नहीं। इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता।

****

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 24 सितंबर, 2024

दैनिक जागरण

संघर्ष के बिना मिली सफलता बेस्वाद होती है

भारत-अमेरिका संबंध

भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा दोनों देशों के संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता का परिचय देने वाली तो है ही, भारत के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय कद को भी रेखांकित करने वाली है। इस यात्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि क्वाड संगठन अब एक ठोस आकार ले रहा है और उसके उद्देश्य भी पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो रहे हैं। क्वाड को और अधिक सशक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी सदस्य देश अर्थात भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया अपने आपसी संबंधों में भी सुधार लाने की दिशा में आगे बढ़ें। क्वाड के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं, उनमें केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता ही नहीं है, बल्कि विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी जारी उथल-पुथल भी है। क्वाड इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि एक ओर रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है तो दूसरी ओर पश्चिम एशिया में भी अशांति बढ़ रही है। क्वाड को एक ऐसे प्रभावी संगठन के रूप में उभरना होगा, जो न केवल स्वयं अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों के प्रति प्रतिबद्ध रहे, बल्कि यह संदेश देने में भी सफल रहे कि दुनिया के सभी देशों को ऐसा करना होगा। लोकतांत्रिक देशों के संगठन के रूप में क्वाड के और अधिक प्रभावी होने की आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अपना प्रभाव एवं अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। विडंबना यह है कि इसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है।

भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा इसका भी सूचक है कि दोनों देशों के संबंध अब एक ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं, जहां आपसी लेन-देन एवं समझबूझ और अधिक बढ़ेगी। इसकी पुष्टि विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रहे आपसी समझौतों से भी होती है। अब इस नतीजे पर पहुंचने के अच्छे-भले कारण हैं कि भारत-अमेरिका मैत्री पर किसी देश में सत्ता परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे समय क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका पहुंचे, जब कहां राष्ट्रपति चुनावों का जोर है। यह लगभग तय है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कोई भी बने, दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होते रहेंगे। यह स्थिति बनी रहे, इसके लिए उन मुद्दों को हल करना भी आवश्यक है, जो दोनों देशों के संबंधों में बाधा बनते रहते हैं अथवा अविश्वास का कारण बनते हैं। यह अच्छा नहीं हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के ठीक पहले अमेरिकी अधिकारियों ने खालिस्तान समर्थकों से मुलाकात करना आवश्यक समझा। इस मुलाकात का उद्देश्य कुछ भी हो, उससे संदेश यही निकला कि अमेरिकी नेतृत्व खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशील नहीं। भारत इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों में किस तरह खालिस्तान समर्थकों को संरक्षण दिया जा रहा है और उन्हें भारत विरोधी गतिविधियां चलाने की छूट सी दी जा रही है।

पुलिस के लिए चुनौती

पंजाब में गैंगस्टरों एवं आतंकियों की ओर से फोन करके रंगदारी मांगने की घटनाओं से लोगों में डर पैदा होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है जिससे पुलिस के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। मोहाली में एक प्रापर्टी डीलर को फोन करके दो करोड़ रुपये मांगे गए, जबकि फार्मास्युटिकल कारोबारी से बिजनेस में हिस्सा देने को कहा गया। दोनों को फोन करने वाले ने अपना नाम गोल्डी बराड़ बताया और मांग पूरी न करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। इसी तरह तरनतारन में एक किसान को फोन करके आतंकी लखबीर के गुर्गे ने पचास लाख रुपये मांगे। रंगदारी देने से इन्कार करने पर घर पर फायरिंग भी की गई। इससे पता चलता है कि असामाजिक तत्वों का दुस्साहस कितना बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी गुरदासपुर एवं तरनतारन में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। तस्करों, गैंगस्टरों एवं आतंकियों का गठजोड़ सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस को यथाशीघ्र इस गठजोड़ को खत्म करना होगा। गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रही है। पिछले दिनों कुछ नाबालिग भी पकड़े गए हैं जो गैंगस्टरों के साथ बारदात में शामिल थे। पैसे का लालच देकर गैंगस्टरों द्वारा नाबालिग से वारदात करवाना ज्यादा चिंता वाली बात है। अभिभावकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, इसलिए अपने बच्चों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। पुलिस को भी लोगों में भरोसा पैदा करना होगा जिससे वे बिना डरे गैंगस्टरों की गतिविधियों की जानकारी दें। गैंगस्टरों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है।

पुलिस को गैंगस्टरों, आतंकियों एवं तस्करों के गठजोड़ को यथाशीघ्र खत्म करना होगा

राहुल की आत्मघाती आक्रामकता

डा. एके वर्मा

राहुल गांधी को समझना होगा कि भारत का जनमानस शिष्ट आचरण, तर्कसंगत विचार और शालीन भाषा पसंद करता है

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाल की अमेरिका यात्रा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक रहे। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों में 'चौकीदार चोर है' और 2024 में 'अदाणी-अंबानी' के सहारे उन्होंने मोदी को उद्योगियों का हितैषी और गरीब विरोधी बताने की नाकाम कोशिश की। इसी वर्ष एक जुलाई को उन्होंने लोकसभा में कहा, '...और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वे 24 घंटे हिंसा-हिंसा, नफरत-नफरत, असत्य-असत्य करते हैं...।' अमेरिका में उन्होंने कहा कि भारत में सिख समुदाय को कड़ा, पगड़ी पहनने और गुरुद्वारा जाने की स्वतंत्रता नहीं है। यह तथ्यहीन और अनर्गल आरोप समाज तोड़ने की कुटिल और निंदनीय साजिश है। विडंबना यह है कि वह अमेरिका में सिखों के मामले में दिए गए अपना बयान पर कायम रहना चाहते हैं।

वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब सिखों का कांग्रेस प्रायोजित कत्लेआम हुआ, तब जरूर सिख समुदाय में असुरक्षा की भावना रही, लेकिन अब वह इतिहास की बात है। राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं और लोग पप्पू' कहकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं। राहुल की मंडली उनकी छवि बदलने के प्रयास में भी लगी है। इसी सिलसिले में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने दो राजनीतिक यात्राएं कीं, जिसका उन्हें लाभ भी मिला। इस चुनाव में कांग्रेस ने 97 सीटें और 21.19 प्रतिशत वोट प्राप्त किए जो, 2019 में प्राप्त हुए करीब 19 प्रतिशत मत और 45 सीटों की तुलना में कहीं अधिक था। चुनाव में राहुल ने लोगों को डराया कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी और अब स्वयं अमेरिका जाकर बोल रहे कि हम 'आरक्षण खत्म करेंगे', जिस पर बाद में लीपापोती का प्रयास भी किया गया। राहुल के इस बयान पर चिराग पासवान और मायावती के अलावा भाजपा ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। विदेश में भारत की छवि खराब करने वाले नेता जैसी छवि राहुल की बन गई है, जिसका फायदा शत्रु देश और विदेशी ताकतें उठाने को व्याकुल बैठी हैं।

हालांकि राहुल की इस राह में तीन अवरोध हैं। पहला, भाजपा और मोदी, दूसरा आइएनडीआइए के घटक दल और तीसरा स्वयं कांग्रेस। इनमें सबसे बड़ा अवरोध कांग्रेस के मोर्चे पर ही है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं, जो कांग्रेस को राहुल से बेहतर नेतृत्व दे सकते हैं, लेकिन नेहरू-गांधी परिवार ने पार्टी पर ऐसा शिकंजा कसा हुआ है कि शीर्ष पद पर कोई भी हो, असल नेतृत्व परिवार का होता है। दूसरा अवरोध आइएनडीआइए के घटक दल हैं, जिनके नेता समय आने पर कड़ी चुनौती दे सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़ नहीं सकती। यदि कांग्रेस को सहयोगी दलों की बैसाखी चाहिए, तो उसे सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा। जिस घटक दल की ज्यादा सीटें आएंगी, वह कांग्रेस से सौदेबाजी करेगा।

प्रतीक सिन्हा

केंद्र में गैर-भाजपा सरकार बनने की स्थिति में यदि कांग्रेस राहुल को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करेगी तो उसे घटक दलों का बंधक बनना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस को घटक दलों से ऐसा समझौता भी करना पड़ेगा कि यदि उसे 2029 के लोकसभा चुनावों में ज्यादा सीटें चाहिए तो विधानसभा चुनावों में घटक दलों के लिए वह बड़ा हिस्सा छोड़ दे। आगामी विधानसभा चुनावों में यह रेखा रुचिकर होगा कि कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है, लेकिन इतना निश्चित है कि राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

राहुल गांधी को सबसे मजबूत चुनौती मोदी और भाजपा से मिलेगी। मोदी-विरोधी आक्रामकता से राहुल को लोकसभा में अधिक संसद्, मत और प्रतिष्ठा तो मिली है। यह कहा जा सकता है कि राहुल की आक्रामकता रंग ला रही है, लेकिन रंग लाने और सत्ता पाने में फर्क है। राहुल की समझना होगा कि भारत का जनमानस शिष्ट आचरण, तर्कसंगत विचार तथा शालीन भाषा पसंद करता है। उन्हें कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनने चाहिए, जिससे एक नेता के रूप में निखरने के लिए वह वांछित रवैया अपना सकें। अभी तक के उनके व्यवहार में लड़कपन की झलक मिलती है, धीर-गंभीर राजनीतिज्ञ की नहीं। नेतृत्व की लड़ाई में व्यक्तिगत छवि का बहुत महत्व होता है। उनकी स्पर्धा मोदी से है। यदि उन्हें राजनीति की जरा भी समझ है तो पता होगा कि देश-विदेश में मोदी की छवि बहुत अच्छी है। क्या आक्रामक, असंयत, अशिष्ट भाषा और बचकाना व्यवहार राष्ट्रीय स्तर पर राहुल को गंभीर और परिपक्व नेता बनने देंगे? अभी तक किसी नीतिगत मुद्दे पर उन्हें गंभीर होते या तर्क करते नहीं देखा गया। एकाध अवसर पर आक्रामक हुआ जा सकता है, लेकिन सख्त तो गंभीर विचार और ठोस तर्क से ही बनती है। ऐसा न हो कि आक्रामकता के सहारे 'पप्पू छवि' से निकलने के प्रयास में उनकी छवि 'नोटोरियस पप्पू' की बने, जिससे उनको एवं कांग्रेस को फायदे के बजाय नुकसान हो जाए?

विरोध की राजनीति विपक्षी दल का एक नैसर्गिक अधिकार है, लेकिन नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी को समझना होगा कि मोदी-विरोध का केवल आंतरिक ही नहीं, वरन बाह्य पहलू भी है। चीन, पाकिस्तान और अनेक देश भारत के शत्रु हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहभागी-जन अपने देश की ही आगे रखते हैं। चाहे अपनी सरकार से उनके कैसे भी संबंध हों, लेकिन राहुल गैर-जिम्मेदाराना ढंग से अपने ही देश को नीचा दिखाते फिरते हैं। आज भारत की छवि सफल लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में बनी है तो विदेशी धरती पर यह कहना कहां तक उचित है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, सरकार संविधान पर हमला कर रही है, मोदी सबको डराते हैं, सरकार उनके विचारों को दबाने का प्रयास कर रही है, सरकार ने संवाद के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं इसलिए उनको यात्रा द्वारा जनता से सीधे संवाद करना पड़ा कि उनकी बजह से सबका डर खत्म हो गया है और भारत में उन्होंने ही सबसे पहली बार 'प्यार का विचार' प्रस्तुत किया है... यह सब भ्रामक, तथ्यहीन और अनर्गल होने के साथ ही आत्मग्लानि से भरा है। यह भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्कृति पर कुठाराघात जैसा है, जिसका फायदा उठाने के लिए अनेक राष्ट्र-विरोधी शक्तियां आतुर होंगी।

(लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

मुसलमानों को फिर से डराने की साजिश

मुख्तार अब्बास नकवी

वक्फ संशोधन विधेयक से केवल उन्हीं को दिक्कत हो सकती है, जो वक्फ संपत्तियों को निजी जागीर मान बैठे हैं

वक्फ बिल में बदलाव का विरोध। एएनआइ

वक्फ संशोधन बिल, 2024 को लेकर एक बार फिर भारत में सौ साल पहले के खिलाफत आंदोलन जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। वक्फ और खिलाफत आंदोलन का चोली-दामन का साथ था। हम वक्फ और खिलाफत आंदोलन के घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो समझ सकेंगे। इसकी शुरुआत 1895 में ब्रिटिश राज की एक न्यायिक कमेटी के कुछ निर्णयों के चलते हुई, जिसमें कहा गया था कि 'वर्तमान वक्फ सिस्टम सर्वाधिक बुरा और हानिकारक है।' यह टिप्पणी ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत भारत सहित कई देशों में प्रचलित वक्फ व्यवस्था पर थी। अन्य देशों ने इसे स्वीकार कर सुधार का रास्ता चुना, लेकिन भारत में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सौदा करने के इरादे से अंग्रेज सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अंग्रेजों की योजना से इसे मुद्दा बनाकर कुछ कट्टरपंथी जमातों ने इस्लाम की रक्षा के नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में विरोध शुरू कर दिया।

प्रथम विश्व युद्ध (वर्ष 1914-18) के बाद आटोमन साम्राज्य और उसकी स्वघोषित इस्लामी खलीफा व्यवस्था के खात्मे से परेशान तुर्किये के लोगों द्वारा 'तुर्किये गणराज्य' की स्थापना को कुछ इस्लामी कट्टरपंथी जमातों ने अंग्रेजों की साजिश और इस्लाम पर हमला प्रचारित कर अंतरराष्ट्रीय इस्लाम बचाओ अभियान शुरू कर दिया। इसका अन्य देशों में तो कोई खास असर नहीं हुआ, पर भारत में यह काफी असरदार दिखा। तब तक जिन्ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बंबई से सदस्य चुने जा चुके थे, जिसे ब्रिटिश हुकूमत में विधायी अधिकार थे। जिन्ना ने अंग्रेजों से साठगांठ कर काउंसिल में 'मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग बिल, 1913' पास करा लिया, जिसका विस्तार और अधिक शक्तियों के साथ 1923 में 'मुसलमान वक्फ एक्ट' के रूप में हुआ। इस तरह अंग्रेजों ने सोची-समझी साजिश के तहत जिन्ना और मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक सियासत का कानूनी हथियार थमा दिया। इसमें कहा गया कि कोई भी मुसलमान अपने परिवार, बच्चों, आश्रितों के आंशिक या पूर्ण समर्थन के लिए वक्फ बना सकता है। यह वक्फ व्यवस्था को निरंकुश बनाने के साथ रजवाड़ों, रियासतों, नवाबों के दान के नाम पर अथाह संपत्तियों को वक्फ का सुरक्षा कवच पहनाकर बचाने और मालिकाना हक कायम रखने की मंशा से प्रभावित था।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद वक्फ मुद्दे को और धारदार बनाने के लिए मुस्लिम लीग और अन्य कट्टरपंथी नेताओं ने भारत में 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई, जिसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया। महात्मा गांधी का सोच था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिंदू-मुसलमान एकजुट होकर लड़ेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम को ताकत मिलेगी, पर खिलाफत आंदोलन का मकसद भारत की आजादी के बजाय देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिये अलग मुल्क की मांग को हवा देने का था। अंग्रेजों ने अपनी बांटो और राज करो की नीति के तहत जिन्ना आदि मुस्लिम नेताओं से साठगांठ कर 1930 में मुसलमान वक्फ एक्ट (रेट्रोस्पेक्टिव) यानी पहले की वक्फ संपत्तियों और व्यवस्था पर भी लागू होने वाला कानून बना दिया। आजादी के बाद वक्फ एक्ट में कई बार संशोधन हुए, पर वे मुख्य रूप से मुसलमान वक्फ एक्ट, 1930 की कापी-पेस्ट ही रहे।

बंटवारे के वक्त भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए, वे जिस जमीन-जायदाद पर ठहरे, आज उन संपत्तियों के मालिक हैं। जो लोग पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए, वे आज भी न मालिक और न किराएदार बन पाए, बल्कि 'अवैध कब्जेदार' बनकर रह गए। वे वक्फ बोर्डों के शोषण का शिकार होते रहते हैं। वे भी इस वक्फ सिस्टम के बड़े हितधारक हैं। उन्हें भी मानवीय न्याय मिलना चाहिए। इसी पहलुओं के मद्देनजर 1954 के वक्फ एक्ट में बोर्ड के सदस्य बनने के लिए सिर्फ मुसलमान होना अनिवार्य नहीं था, मगर 2012-13 में संशोधन कर 'मात्र मुस्लिम' कर दिया गया। आज वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कुछ लोग वैसे ही भय-भ्रम का माहौल बना रहे हैं, जैसा खिलाफत आंदोलन के नाम पर इस्लाम बचाओ मुहिम के नाम पर किया गया था।

खिलाफत आंदोलन का भारतीय मुसलमानों से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। उस आंदोलन की मांग थी कि तुर्किये खिलाफत सुरक्षित रहे, तुर्किये के धार्मिक स्थल सुरक्षित हों, तुर्किये की सीमाएं प्रथम विश्व युद्ध से पहले वाली बहाल हों। इन तीनों मांगों में भारत, भारतीय मुसलमानों का कहीं भी हित नहीं था, लेकिन खिलाफत आंदोलन के जरिये इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को बरगलाकर जिन्ना एंड कंपनी ने अपने निहित और सियासी स्वार्थ साधे। आज फिर देश में वैसा ही माहौल खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इसमें जाकिर नाइक जैसे कुछ षड्यंत्रकारी बहुत सक्रिय हैं, जो वक्फ सिस्टम में अहम सुधारों से डरे हुए हैं। उन्हें भी मालूम है कि वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 किसी मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़े, धार्मिक स्थलों या इस्लामी कर्तव्यों के लिए न खतरा है, न रोड़ा है, बल्कि इसका उद्देश्य देश में वक्फ सिस्टम को सशक्त, पारदर्शी, प्रभावी और सामाजिक सशक्तीकरण का संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। हां, उन लोगों के लिए जरूर चिंता की बात हो सकती है, जो वक्फ संपत्तियों को अपनी निजी जागीर और परिवार की प्रापर्टी मान बैठे हैं। शायद वे वक्फ संपत्तियों द्वारा समाज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए सदुपयोग के विचार से विचलित हैं। इसीलिए फिर वक्फ के नाम पर देश के मुस्लिम समुदाय को डराने की साजिश कर रहे हैं। इनसे मुस्लिम समुदाय को सावधान रहना होगा।

(लेखक पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन की शांति का मार्ग क्षमा

पूरे दिन हम दूसरों की बुराइयों, कमियों, कमजोरियों, दुर्व्यवहारों एवं दुश्चेष्टाओं की कितनी सारी स्मृतियां जमा करके रखते हैं। ये हमारे सुखमय जीवन जीने के लिए बाधक होती हैं। ऐसी पीड़ादायक अवस्था से निजात पाने का एकमात्र सरल उपाय है, 'क्षमा भाव।' क्षमाशीलता ही एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने मन से घृणा, द्वेष, नाराजगी इत्यादि जैसे भावों को दया, करुणा एवं सहिष्णुता में परिवर्तित कर सकते हैं। विद्वान एवं गुणीजनों ने सदैव 'भूलो और माफ करो' का सूत्र अपने जीवन में अपनाकर आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त किया और दूसरों को भी प्रेरित करवाया है। जब तक हम भूलेंगे नहीं तब तक क्षमा भी नहीं कर सकेंगे और यदि क्षमा नहीं करेंगे तो भुला भी नहीं सकेंगे और यदि भुला नहीं सकेंगे तो हमारे जीवन में निखार आएगा ही नहीं और हम सुख-चैन की नींद सो भी नहीं पाएंगे।

क्षमा न कर सकना अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, परंतु केवल दूसरों को ही क्षमा करना पर्याप्त नहीं है, अपितु हमने यदि कुछ अनिष्ट, अयुक्त, अमर्यादित अथवा अभद्रतापूर्ण व्यवहार किसी से किया हो तो हमें भी दूसरों से उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अथवा खेद प्रकट करना चाहिए, वरना न तो हमारा अभिमान मिटेगा और न ही बुरा करने की हमारी आदत मिटेगी। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल और हल्का नहीं हो पाएगा।

शायद ही कोई होगा जिसने अपने जीवनकाल में कभी दूसरों को हानि न पहुंचाई हो या दुर्व्यवहार न किया हो या निंदा-चुगली न की हो। इतना सब करने के पश्चात क्षमा मांगकर हल्का होना ही उचित है, क्योंकि ऊपरवाला हर कर्म का हिसाब लेता है। उसकी अदालत में किसी की सिफारिश काम नहीं करती है। ऐसे में समझदारी दूसरों की बुराई मन से भुलाने और अपनी बुराई के प्रति क्षमाभाव प्रकट करने में ही है।

राजयोगी ब्रह्माकुमार निकुंज जी

सेमीकंडक्टर चिप का बढ़ता महत्व

डा. शशांक द्विवेदी

उम्मीद है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित होने के बाद भारत विपक्ष बनाने के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की एक नई राह खोल दी है। इस दौरान अमेरिका के साथ हुए एक अभूतपूर्व समझौते के तहत भारत को अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र मिलेगा। यह अमेरिकी सशस्त्र बलों, सहयोगी सेनाओं और भारतीय रक्षा बलों की चिप की आपूर्ति करेगा। यह संयंत्र भारत में 2025 में स्थापित होगा। इसे शक्ति का नाम दिया जाएगा। इससे पहले सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मोदी सरकार ने पिछले दिनों सेंटर नेपड़ा में तीन दिवसीय सेमीकान इंडिया का आयोजन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में हुए विकास को दुनिया को दिखाना और अन्य देशों को भारत में आकर अपनी फैक्ट्री खोलने और निवेश के लिए प्रेरित करना था।

भारत सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया में एक केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है। वर्तमान में सबसे अधिक सेमीकंडक्टर बनने वाला देश ताइवान है, जिस पर चीन अपना हक जताता रहता है। इसलिए भारत को इसपर तेजी से काम करना होगा। भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 2026 तक 80 बिलियन डालर और 2030 तक 110 बिलियन डालर को पार करने की उम्मीद है। इससे यह साफ होता है कि चिप निर्माण भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत के लिए बहुत मायने रखता है। फिलहाल 90 प्रतिशत चिप की आपूर्ति के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। कोरोना के बाद सेमीकंडक्टर निर्माण में कमी आने के बाद भारतीय आटो मोबाइल समेत अन्य तकनीकी उद्योग प्रभावित हुए थे, क्योंकि महंगी कारों से लेकर स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण कुछ ही देशों में केंद्रित है। ताइवान दुनिया के 60 प्रतिशत से ज्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है और दक्षिण कोरिया 100 प्रतिशत सबसे उन्नत चिप (10 नैनोमीटर से कम) बनाता है।

सेमीकंडक्टर आटोमोबाइल, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीकाम और सैन्य प्रणालियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार का लक्ष्य देश के भीतर यथासंभव अधिक से अधिक सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करना है। केंद्र सरकार राज्यों सरकार के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर यूनिट को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और नीतिगत सहायता प्रदान कर रही है। सिंगापुर से भी सेमीकंडक्टर उत्पादन में सहयोग के लिए चार समझौते हुए हैं। भारत को चिप निर्माण के जरूरी सिस्टम बनाने के लिए भारत में संबंधित उद्योगों को जोड़ने पर भी तत्काल काम करना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय क्षमता को भी बढ़ाने की रूरत है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

यूनिवर्सल हेल्थ बीमा का सपना

'आयुष्मान भारत का मिशन' शीर्षक से लिखे आलेख के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई आयुष्मान योजना के छह साल पूरे होने पर इसके लाभ बताने के साथ इसे और मजबूत करने की बात कही है। हाल में आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए 70 साल से ऊपर के हर वर्ग के बुजुर्गों को इसमें शामिल किया गया। यह सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है। उम्मीद है भविष्य में सरकार इस योजना का और विस्तार करेगी जिससे देश के हर नागरिक को इसका लाभ पहुंचे। आयुष्मान योजना आज देश में गरीब लोगों की जान बचा रही है। इसके अभाव में पहले वे महंगे इलाज का बोझ न उठा पाने के चलते दम तोड़ रहे थे। अब देश की बहुत बड़ी आबादी इलाज की चिंता से मुक्त होकर जीवनयापन कर रही है। अब वह अपना ध्यान रोजी रोटी कमाने और परिवार के उत्थान पर लगा रही है। इससे एक फायदा यह हुआ है कि किसी बीमारी की स्थिति में परिवार के सदस्य संबंधित व्यक्ति को बोझ की तरह नहीं देख रहे हैं। हालांकि देश में अभी भी बहुत से ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार को अब इसमें जरूरी सुधार कर 60-70 साल के लोगों को भी इसके दायरे में लाना चाहिए। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जो 60-70 साल के हो जाने पर भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनको सस्ता इलाज मिल सके। केंद्र सरकार को धीरे-धीरे इस योजना का विस्तार कर सभी देशवासियों को इसके दायरे में लाना चाहिए ताकि यूनिवर्सल हेल्थ बीमा का सपना पूरा हो सके। इससे स्वस्थ समाज बनाने में मदद मिलेगी।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

चीन की कथनी और करनी में फर्क

'अक्सिचसनेय चीन का मुकाबला' शीर्षक आलेख में डा. ऋषि गुप्ता ने चीन की करनी और कथनी पर विश्वास नहीं करने की सलाह दी है। हुए कहा है कि चीन मोदी सरकार से असहज है, जबकि नेहरू-इंदिरा के युग में चीन एक मामूली स्थिति में रहा, जो अब उसे मुश्किल लग रहा है। सैन्य विश्लेषक बताते हैं कि वर्ष 2020 में गलवन घाटी में दोनों देशों के बीच हुई झड़पों में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को छक्के छुड़ाए थे। उसके बाद चीन को होश आ गया कि यह बदली हुई भारत की सैन्य ताकत है। बीते दिनों अमेरिका में क्वाड की बैठक में क्वाड नेताओं ने चीन का सीधे नाम लिए बिना दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के जलक्षेत्र की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई तथा उस क्षेत्र में तटरक्षक और समुद्री मिलिशिया जहाजों के 'खतरनाक' उपयोग की निंदा की। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता पर साझा चिंताओं के मद्देनजर क्वाड नेताओं ने ऐसी किसी भी 'एकतरफा' कार्रवाई का कड़ा विरोध किया, जो बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है। क्वाड अमेरिका, भारत, जापान और अस्ट्रेलिया सदस्य देशों का एक सशक्त शिखर मंच है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में चीन पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत हमारी प्राथमिकता है। मोदी ने कहा कि क्वाड नेता ऐसे समय में एकत्र हुए हैं, जब पूरी दुनिया तनाव और संघर्ष से घिरी हुई है। ऐसे समय में क्वाड का अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मिलकर काम करना पूरी मानव जाति के लिए अहम है।' उन्होंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के पक्ष में हैं। हांगकांग के 'साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट' ने अपनी खबर में कहा कि किसी भी मायने में क्वाड शिखर सम्मेलन चार देशों के ढांचे के लिए एक उल्लेखनीय बदलाव का संकेत है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

मेलबाक्स

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
बी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 24 सितम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

इन्सान को यह देखना चाहिए कि क्या है, यह नहीं कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए
-अल्बर्ट आइंस्टीन

चीन को घुड़की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) किसी के खिलाफ नहीं है। बल्कि नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था व संप्रभुता के सम्मान के पक्ष में है। यह अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान के साथ भारत को मिलाकर बनाया गया संगठन है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा, स्वतंत्र, खुला, समावेशी व समृद्ध हिंद-प्रशांत हमारी प्राथमिकता है। किसी देश का नाम लिये बगैर उन्होंने जोड़ा, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता का सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता व सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण तरीके से हम समाधान करने के समर्थन में हैं। प्रधानमंत्री का इशारा परोक्ष रूप से चीन की तरफ था। चूंकि क्वाड सदस्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में खुले व्यापार के समर्थक हैं। जिसका

सकारात्मक व स्थाई प्रभाव दिख रहा है। लंबे समय से चीन 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति' के तहत चीन-हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाहों व सैन्य ठिकानों को विकसित कर रहा है। इसके चार प्रमुख समुद्री लोकतांत्रिक देशों के तौर पर यह संगठन शांति व स्थिरता बनाए रखने का कार्य कर रहा है। जो वैश्विक सुरक्षा व समृद्धि के लिए अनिवार्य माना जा रहा है। स्पष्ट रूप से चीन लगातार हमारे करीबी पड़ोसियों म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल, मालदीव जैसे मुल्कों में वर्चस्व बढ़ा कर भारत को घेरने के प्रयास कर रहा है। हालांकि चीन के साथ सीमा विवाद में देश को अमेरिका व जापान का समर्थन प्राप्त है। साथ ही जापान लगातार भारत को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय मदद भी कर रहा है। जो चीन का मुकाबला करने में खास मददगार साबित हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, क्षमता निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्वाड के काम का लाभ देश को परोक्ष व प्रत्यक्ष तौर पर निरंतर प्राप्त हो रहा है। मोदी द्वारा बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर प्रमुखता से जिक्र करना तथा विचारों का आदान-प्रदान असरकारी हो सकता है। बहुपक्षीय व द्विपक्षीय स्तरों पर वैश्विक तरक्की, शांति व सुरक्षा को लेकर भारत की प्रतिबद्धता व विचारों का सीधा असर दुनिया के समक्ष शीघ्र ही स्पष्ट होता जाएगा। जो अस्थिरताकारी व एकतरफा कार्रवाई का विरोध कर सकेगा व यथास्थिति को बदलने की सकारात्मक प्रयास होते नजर आ सकेंगे।

साजिश का पर्दाफाश जरूरी

देश के कई हिस्सों में ट्रेन को बे-पटरी करने की साजिश वाकई चिंता का सबब है। आए दिन किसी-न-किसी इलाके से पटरी पर विस्फोटक सामग्री या लोहे के रॉड रखकर ट्रेन को पलटाने की खबरें सुर्खियों में हैं। एक दिन पहले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सेना के जवानों को ले जा रही ट्रेन में विस्फोट की कोशिश की गई थी। वहीं कानपुर में भी एक ट्रेन को गिराने की साजिश रची गई थी। इस तरह की घटनाओं से यात्रियों के मन में डर बैठ गया है जो निःसंदेह देश के लिए अच्छे संकेत तो कतई नहीं हैं। हालांकि सरकार इसे लेकर सतर्क है और सख्ती से इसे कुचलने को लेकर बेहद गंभीर भी है। इसकी गहराई से तफ्तीश भी कराई जा रही है, मगर यक्ष प्रश्न यही कि आखिर देश भर में लाखों किलोमीटर में फैली रेल पटरियों पर क्या 24 घंटे निगरानी की जा सकती है? आखिर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उन्हें ऐसी करतूतों के लिए कौन

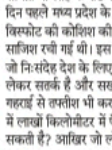

तैयार कर रही है, इसकी फंडिंग कहां से हो रही है और अब तक ऐसी कितनी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, इसकी तह तक जाना सरकार के लिए निहायत जरूरी बन पड़ा है। रोज-रोज ऐसी साजिशों का न केवल भंडाफोड़ होना चाहिए बल्कि ऐसा करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके बाद कोई भी शख्स ऐसा करने के बारे में सोचने से डरे। रेल परिचालन में पहले इस तरह की घटना कभी नहीं देखी गई। हां, हादसे जरूर हुए मगर साजिश के तहत रेल पलटाने की इक्का-दुक्का खबरें ही सामने आई। मगर इस तरह का ट्रेंड वास्तव में खतरनाक है। यह भी देखा गया है कि ज्यादातर साजिशों की खबरें उत्तर भारत से मिल रही हैं। लिहाजा, सरकार को अब ज्यादा तैयारी और सतर्कता के साथ इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। देश में रोजाना करीब 2.4 करोड़ से 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की आबादी के बराबर है। भारत में रेलवे का नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है। यहां रोजाना करीब 22,593 ट्रेनें चलती हैं, जिनमें से 13,452 ट्रेनें यात्रियों के लिए हैं। अब इतनी सारी ट्रेनों पर नजर रखना या उनकी चौकसी करना वाकई दुष्कर काम है। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा करने के लिए उपाय तलाशने जरूरी हैं। उम्मीद है कि रेल महकमा इस बारे में कुछ बेहतर करने के उपाय तलाश रहा होगा। देश के दुश्मनों को सबक सिखाना वक्त की मांग है।

ऊर्जा क्षेत्र / अमित बैजनाथ गर्ग

करने होंगे नये प्रयोग

दुनिया में एक बार फिर ऊर्जा क्षेत्र को लेकर चर्चा हो रही है। यह ऊर्जा क्षेत्र के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। आखिर क्यों बार-बार एनर्जी सेक्टर पर इतनी गंभीरता से बातचीत की जा रही है? क्यों वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? असल में दुनिया ऊर्जा के क्षेत्र में संकटों का सामना कर रही है। उभरते ऊर्जा संकट, घटते जीवाश्म ईंधन संसाधनों और उच्च तेल की कीमतों के साथ जलवायु परिवर्तन की चिंताओं ने बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय, वैकल्पिक, पर्यावरण अनुकूल और कार्बन तटस्थ ईंधन के विकास की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। अधिकांश ऊर्जा संकट स्थानीय कमी, युद्ध और बाजार में हेरफेर के कारण हुए हैं।

भारत की बात करें, तो इसके ऊर्जा संकट से निपटने की राह में कई चुनौतियां हैं। भारत के पास कोयला, तेल और गैस जैसे सीमित ऊर्जा संसाधन ही मौजूद हैं और यह अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है। परिणामस्वरूप भारत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है, जैसे कि सौर, पवन और जल विद्युत। वहीं देश के ऊर्जा क्षेत्र में अभी अपर्याप्त निवेश है। देश के ऊर्जा क्षेत्र को अपने बुनियादी ढांचे में सुधार और अपनी ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के लिए वृहद निवेश की आवश्यकता है, लेकिन सरकार और निजी क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं कर पा रहे हैं। देखा जाए तो देश में ऊर्जा क्षेत्र में त्वरित सुधारों की दरकार है। सबसे पहले तो आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू कोयले की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देना होगा। इसे कोयले के कैलोरी मान को बढ़ाने और राख की मात्रा को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश कर प्राप्त किया जा सकता है। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना होगा। सरकार को प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को प्रेरित करना चाहिए। पिछले कुछ सालों में लोगों में ऊर्जा दक्षता को लेकर चेतना बढ़ी है, लेकिन अभी भी जागरूक होने की दरकार है। इस तरह छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बिजली की बचत कर सकेंगे।

खेला जा रहा इस्लामिक कार्ड

भारत भारत में मुसलमानों की स्थिति पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई द्वारा दिया गया बयान इन दिनों चर्चा में है। भारत-ईरान संबंधों में जहर घोलने वाले इस बयान में खामेनेई ने कहा है कि 'हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते, अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर मुसलमानों द्वारा झेली जा रही पीड़ा के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं।' एक्स पर डाली गई इस पोस्ट के जरिए खामेनेई विश्व समुदाय खासकर इस्लामिक जगत को यह बताना चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ रही है। हालांकि, भारत ने खामेनेई की बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत की आलोचना करने वाले देशों को किसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले अपने स्वयं के गिरेबान में झांक लेना चाहिए।

भारत के ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। अब जब कि ईरान विश्व समुदाय में अलग-थलग पड़ा है, भारत आज भी ईरान के साथ खड़ा है। अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना न केवल भारत ने ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते कायम रखे बल्कि उन्हें और अधिक मजबूत किया है। ऐसे में सवाल यह है कि खामेनेई भारत-ईरान संबंधों में पलीता क्यों लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्लामिक जगत के पैरोकार बनने की चाह में खामेनेई ने भारत को उन देशों के साथ जोड़ दिया है, जहां मुस्लिम उत्पीड़न की घटनाएं होती रही हैं।

भारत-ईरान संबंध

डॉ. एन.के. सोमानी

अहम बात यह है कि उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया जहां उइगुर मुसलमानों को नमाज पढ़ने और रोजे रखने तक की इजाजत नहीं है। साल 2021 में ब्रिटेन के एक ट्रिब्यूनल ने कहा था कि चीन अपने पश्चिमी प्रांत में उइगुर मुस्लिमों का नरसंहार कर रहा है। ट्रिब्यूनल ने उइगुर मुस्लिमों को लेकर चीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि चीन की सरकार द्वारा उइगुर मुस्लिमों की आबादी को कम करने के लिए उनकी जबरन नसबंदी की जा रही है, जो एक नरसंहार है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अंग्रेजी दैनिक 'द हेराल्ड सन' ने ऑगर्न

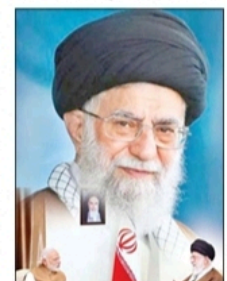

और कठोर यातनाएं आम बात हो गई है, इसके बावजूद खामेनेई मुंह में दही जमाए बैठे हैं। उइगुरों के उत्पीड़न पर न सऊदी बोल रहा है और न ही पाकिस्तान। यह पहला अवसर नहीं जब खामेनेई का भारतीय मुसलमानों के प्रति प्रेम उमड़ा है। 2020 के दिल्ली दंगों के बाद भी उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार हुआ है। कश्मीर मुद्दे पर भी खामेनेई कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। साल 2017 में खामेनेई ने कश्मीर की तुलना गाजा, यमन और बहरीन से की थी। अगस्त 2019 में अनु. 370 हटाने के कुछ दिन बाद खामेनेई ने लिखा था कि हम कश्मीर में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं।

अब रही बात भारत-ईरान संबंधों की तो ईरान के साथ भारत के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। 15 मार्च, 1950 से ही दोनों देशों के बीच राजनियक संबंध हैं। 1983 में भारत-ईरान संयुक्त आयोग की स्थापना के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध और रक्षा सहयोग की नींव पड़ी। ईरान न केवल हमारी तेल और गैस जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि मध्य एशिया में कनेक्टिविटी में भारत का मददगार है। हाल ही में दोनों देशों के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर महत्वपूर्ण डील हुई है। चाबहार के जरिए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा। चाबहार को अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण व्यापार गलियारे (आईएनएसटीसी) के साथ भी जोड़ने की योजना है।

साल 2003 में भारत और ईरान ने ईरान और मध्य एशियाई देशों से खाड़ी और फिर भारत और अन्य देशों में तेल पहुंचाने की रणनीति के तहत चाबहार को विकसित करने के लिए सम्मझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अतीत में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा तेहरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण अगले कई सालों तक इस परियोजना को शुरू नहीं किया जा सका। वर्ष 2015 के परमाणु समझौते के बाद अमेरिकन प्रतिबंधों में ढील दी गई और उसी साल भारत ने इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2016 में पीएम मोदी की ईरान यात्रा के दौरान समझौते को अमली जामा पहनाया गया, लेकिन वर्ष 2018 में ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण भारत के सहयोग पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि, साल 2019 में भारत को चाबहार बंदरगाह के प्रयोग का अधिकार मिल गया था लेकिन प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण करवाने की शर्त के कारण भारत चाबहार को लेकर कोई दीर्घकालिक रणनीति बनाने एवं उसके प्रयोग के लिए आश्वस्त नहीं था।

अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के 15 वें शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहीम रईसी से चाबहार पर दीर्घकालिक अनुबंध के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर चर्चा की। चर्चा के दौरान दोनों नेता मध्यस्थता खंड को हटाने पर सहमत हुए। इस सहमति के बाद 13 मई, 2024 को दीर्घकालिक अनुबंध का मार्ग प्रशस्त हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत ने ईरान के साथ अपने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों को ध्यान में रखते हुए आपसी संबंध बेहतर बनाने पर ही जोर दिया है, लेकिन अब सर्वोच्च नेता खामेनेई एक बार फिर भारत के विरुद्ध जहर उगलकर भारत-ईरान रिश्तों में खटास पैदा करते दिख रहे हैं। खामेनेई को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस्लामिक दुनिया के खैरख्वाह बनने की लालसा में भारत के साथ संबंधों को ताक पर रखना उचित नहीं होगा।

(लेखक के निजी विचार हैं)

भारत ने ईरान के साथ अपने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों को ध्यान में रखते हुए आपसी संबंध बेहतर बनाने पर ही जोर दिया है, लेकिन अब सर्वोच्च नेता खामेनेई एक बार फिर भारत के विरुद्ध जहर उगलकर भारत-ईरान रिश्तों में खटास पैदा करते दिख रहे हैं। खामेनेई को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस्लामिक दुनिया के खैरख्वाह बनने की लालसा में भारत के साथ संबंधों को ताक पर रखना उचित नहीं होगा

छोटे शहरों और कस्बों के 40% लोग रोजाना करते हैं डिजिटल भुगतान

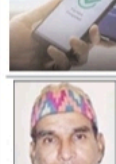

- देश के तीसरे दर्जे के शहरों से लेकर छोटे कस्बों में 40 फीसद से ज्यादा उपभोक्ता दैनिक आधार पर डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं जबकि 45 फीसद लोग दो दिन में एक बार इसका इस्तेमाल करते हैं
- भारत में डिजिटल भुगतान की स्थिति पर जारी 'रेज इंडिया' की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। यह रिपोर्ट कुल 2,240 उत्तरदाताओं के बीच कराए गए सर्वेक्षण पर आधारित है
- उत्तरदाता देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 8 राज्यों के 16 जिलों से थे जिनमें 1,184 उपभोक्ता और 1,056 कारोबारी थे

(स्रोत : मीडिया रिपोर्ट्स)

एक मार्क्सवादी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेपाल का नेतृत्व पहले से ही एक कम्युनिस्ट के हाथ में है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में सैन्य समर्थित, अमेरिका समर्थित शासन व्यवस्था है। मालदीव में इस्लामवादी रुझान वाला राष्ट्रपति है और म्यांमार में विद्रोहियों को अमेरिका की तरफ से सैन्य सहायता का भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

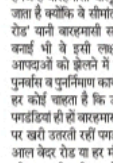

जलवायु बदलाव | वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

आघात से आहत होती सड़कें

इस समय एक ध्यान देने की बात यह है कि उत्तराखंड, हिमाचल व जम्मू-कश्मीर में अधिकांश राजमार्ग जो बाधित हैं या धंस रहे हैं अथवा जिन पर खण्ड-खण्ड हो भूखण्ड गिर जाते हैं उनमें व सड़कें भी हैं जिन्हें बारहमासी चालू रखना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि वे सीमांतों को छूती हैं। इनका 'आॅल वेदर रोड' यानी बारहमासी सड़क होना अपेक्षित है। निसन्देह बनाई भी वे इसी लक्ष्य से बनाई गई होंगी। मौसमी आपदाओं को झेलने में समर्थ सड़कें आपदाओं में राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों को भी आसान कर देती हैं। वैसे हर कोई चाहता है कि उसके आवागमन की राह चाहे वे पगडंडियां ही हों बारहमासी हों। समय असमय की चुनौतियों पर खरी उतरती रहीं पगडंडियां इसकी साक्षी हैं। आज की आल वेदर रोड या हर मौसम में खरी उतरने वाली सड़कों की चाहत भी उसी क्रम में है।

संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास 2030 के लक्ष्यों (एसडीजी) में भी सड़क परिवहन व उससे जुड़े इनफ्रास्ट्रक्चर्स को महत्वपूर्ण मानते हुए सड़क परिवहन तथा पुल सड़कों जैसे इनफ्रास्ट्रक्चरों को जलवायु बदलाव के कुप्रभावों से बचाने और उनके अनुकूलन पर काम करने का आह्वान भी किया गया है, जिससे जलवायु बदलाव के आघात से सड़कें कम आहत हों। धरा का बढ़ता तापमान सड़कों पर भी असर डाल रहा है। गरम होती धरा में पिघलते ग्लेशियरों के साथ पिघलती सड़कों पर भी संकेत किया जा रहा है। यह सामयिक भी है। विश्व में अधिकांश पक्की सड़कें जो कोलतार से ही बनतीं रहीं हैं तेज गर्मी में पिघलने लगती हैं। उत्तर ध्रुवीय प्रदेशों व सदैव बर्फ से ढके रहने वाले क्षेत्रों में जहां वाहन परिचालन वर्फ की सड़कों पर होता है बढ़ते तापक्रम में वर्फ की सड़कें गलने लगती हैं। बारहमासी सड़कों की राह में कई चुनौतियां भी हैं। अति की गर्मी, अति की ठंड, अति की बरसात के साथ जहां बरसात नहीं होती थी वहां बरसात होने लगी है। अतः सड़कों को बारहमासी बनाने के डिजाइन और सामग्री चयन में भी अनिश्चितता आ गई है। जलवायु बदलाव के संगाने के बीच पहले की बनी सड़कों के आसपास का भी मौसम वैसा नहीं रह गया है जैसा उनके बनने के समय था। अतः पहले से बनीं सड़कों को भी आॅल वेदर रोड बनाने के लिए उसी तरह काम किए जाने की जरूरत है। जैसे हम उन भवनों को जो

भूकम्प अवरोधी नहीं हैं; रिट्रोफिटिंग कर भूकम्प सहने लायक बनाते हैं। बारहमासी सड़कों के पुलों को भी बारहमासी होना है। बाढ़, नींव कटाव, पुलों के नजदीक अवैध खनन के अलावा जलवायु बदलाव के दौर में पुल के संदर्भ में एक अन्य तरह की चुनौती भी आ रही है। चूंकि नदियां अपनी राह बदल रहीं हैं इसलिए कई बार पुल निष्प्रयोजन भी हो रहे हैं। सरवाई यह भी है कि हर मौसम पर खरी रहने वाली सड़क भी हर मौसम में यातायात की गारंटी नहीं हो सकती है। सड़कें भले ही मौसमी मार झेल ले उनका कुछ न बिगड़े परंतु विपरीत मौसम की मार वाहन या यात्री झेलने में असमर्थ रहते हैं। उन्हें आगे न बढ़ने की चेतावनियां भी देनी पड़ती है। उदाहरण के लिए आयरलैंड में वाहन चालकों को तेज हवाओं की चेतावनी देते हुए सीमित गति रखने को कहा जाता है। समुद्री के पास जो सड़कें हैं उनमें तूफानी हवाओं और लहरों में यातायात न जारी रखने की चेतावनियां दी जाती हैं। इसी प्रकार सुरंगों के मुहानों पर वर्फ जम जाती है तो सुरंगों का तो कोई नुकसान नहीं होता है किंतु यातायात बाधित हो जाता है। वैज्ञानिक राय है कि बारहमासी सड़कों के बगल से या भीतर से जो गैस पाइपें, सीवर लाइनें, बिजली की तारें पानी की पाइपें आदि गुजरती है या गुजरेंगी जलवायु बदलाव के बीच गिरते बढ़ते तापक्रम में वे कैसी प्रतिक्रियाएं पैदा करती हैं उनका भी असर निर्माण सामग्री चयन के दौरान संज्ञान में रखा जाना चाहिए। सतत विकास व जलवायु बदलाव के प्रत्युत्तर में सड़क इकीसवीं सदी में बनाई जा रहीं हो तो इन बातों पर भी ध्यान दिया जाना अपेक्षित है कि उनसे जलवायु बदलाव से जुड़ी समस्याएं और न बढ़ें, जैव विविधता पर संकट न आए और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े।

प्राकृतिक संसाधनों का कम-से-कम उपयोग हो पर्यावरण हानि कम से कम हो। शोर कम हो। ईंधन की खपत कम हो आदि। विडंबना है कि जलवायु बदलाव अनुकूलन के प्रत्युत्त स्वरूप जो बारहमासी सड़कें बनाई जा रहीं हैं आपेक्षित रूप से ग्रीन रोड होने के बजाय उनके निर्माण में कतिपय संवेदनशील क्षेत्रों में भी हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं। भूमिगत जलस्रोत प्रणालियां ध्वस्त की जाती हैं। हजारों टन मलबा नदियों में डाल दिया जाता है। जैवविविधता के प्रति भी संवेदनशीलता नहीं बरती जाती है व निर्माण के दौरान कम-से-कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वास्तव में आल वेदर रोड से ज्यादा जरूरी आल टाइम उपयोग की सड़कों पर काम करने की जरूरत है। सड़कों पर पर्याप्त रोशनी के लक्ष्यों पर तो अभी बात ही नहीं हो रही है। राजनैतिक कारणों से कमजोर भूभर्भीय संरचनाओं पर सड़कों के बनाने के दबाव से भी उबरने की जरूरत है।

स्वामित्व | ओशो

मालिकियत! इसलिए हिंदू संन्यासियों ने संन्यासी का नाम स्वामी चुना है, लेकिन कैसा स्वामित्व? मकान का, धन का, दुकान का स्वामित्व? नहीं, क्योंकि वह तो सिर्फ धोखा है। तुम बनते हो गुलाम और स्वामी होने का खयाल रखते हो! तुम बनते हो दास और सोचते हो कि सम्राट हो गए! सुना है मैंने, मुसलमान फकीर फरीद एक गांव से गुजरता था। और एक आदमी एक गाय को रस्सी से बांध कर घर की तरफ ले जाता था। तो फरीद रुक गया, उसने अपने शिष्यों से कहा, घेर लो इस आदमी को और इस गाय को, और तुम्हें मुझे कुछ शिक्षा देनी है। तो वह आदमी थोड़ा चौंका। उसने कहा कि मुझे घेरने की क्या जरूरत है? उसने कहा कि तुम चुप रहो, तुमसे हमें कुछ करना नहीं, सिर्फ मेरे शिष्यों को शिक्षा देनी है। और फरीद ने कहा कि शिष्यो, मैं पूछता हूं इन दोनों में मालिक कौन है? गाय या यह आदमी? शिष्यों ने कहा कि आप भी क्या पूछते हैं? जाहिर है कि आदमी मालिक है। क्योंकि गाय उसकी संपत्ति है और गले में उसने उसके फंदा डाला है। तो फरीद ने कहा कि मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूं अगर हम बीच की रस्सी काट दें और गाय भाग खड़ी हो, तो गाय के पीछे यह आदमी दौड़ेगा कि गाय आदमी के पीछे दौड़ेगी? उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह आदमी गाय के पीछे दौड़ेगा। तो गाय इस आदमी को नहीं खोजेगी? यह आदमी गाय को खोजेगा? तो फिर मालिक कौन है? तो फरीद ने कहा कि यह रस्सी तुम्हें दिखाई पड़ती है गाय के गले में, वह इस आदमी के गले में है। वस्तुएं हमारे गले में फंदा कस लेती हैं। जिनके हम मालिक होते हैं, उनके हम गुलाम हो जाते हैं। जरा खयाल करें! हमारे मुल्क में पति अपने को स्वामी कहते हैं। उनसे बड़ा गुलाम खोज सकते हैं आप? स्वामी हैं वे। पत्नी जब उनको पत्र लिखती है तो उसमें स्वामी लिखती है और नीचे दस्तखत करती है, आपकी दासी। और सब भलीभांति जानते हैं कि कौन दास है और कौन मालिक है। स्त्रियां होशियार हैं, वे राजी हैं, कि ठीक, दस्तखत ही करने हैं दासी के! चलेगा, लेकिन असलियत में कौन मालिक है? पति तब तक गुलाम रहेंगे, जब तक वे मालिक होने का खयाल रखते हैं। जब तक उनको खयाल है कि पत्नी के स्वामी होना है, तब तक वे शब्दों में स्वामी बने रहें, वे गुलाम रहेंगे। जो भी मालिक बनने की दूसरे के ऊपर कोशिश करेगा, वह गुलाम हो जाएगा। सब तरह की मालकियत बाहर की दुनिया में गुलामी लाती है।

रीडर्स मेल

आयुष्मान योजना में सुधार हो

देश को मँहगे इलाज की सुविधा देने के लिए जो केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना आरंभ कि थी, उसके छह साल पूरे हो गए। इन छह वर्षों में यह योजना कितनी कामयाब रही इस पर सभी के अपने अपने विचार हो सकते है, लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में जो आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए इस योजना के अंतर्गत 70 साल से ऊपर हर वर्ग के बुजुर्गों को इसमें शामिल किया यह सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है। उम्मीद है कि भविष्य में सरकार इस योजना का विस्तार और करेगी जिससे देश के हर नागरिक को इसका लाभ पहुंचेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि भारत में प्रति व्यक्ति औसतन लगभग 6500 रुपए बीमारियों पर ही बर्बाद होता है। आयुष्मान योजना से पहले हमारे देश में बहुत से लोग गरीबी के और महंगा इलाज के कारण दम तोड़ चुके होंगे, लेकिन आयुष्मान योजना ने बहुत से गरीब लोगों की जान भी बचाई होगी, लेकिन देश में अभी भी बहुत से ऐसे जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा होगा। सरकार को इस योजना की कमियों का बारीकी से जानना चाहिए ताकि इसका लाभ हर जरूरतमंद को मिल सके। आयुष्मान कार्ड जनगणना 2011 के डेटा के आधार पर बनाएं जा रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत से गरीब नहीं आ रहे क्योंकि शायद उनका 2011 का डेटा सरकारी तंत्र में अपडेट नहीं है। सरकार को इस कमी को तत्काल प्रभाव से दूर करना होगा।

राजेश चौहान, जालंधर, पंजाब

बन-बिगड़ रहे समीकरण

हरियाणा चुनाव में बागियों को कांग्रेस-भाजपा के अधिकतर वे पूर्व विधायक उकसा रहे हैं, जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला है। कुछ निर्दलीय होकर चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चुनावी मुकाबला काफी रोमांचक होता जा रहा है। वाणी पार्टी प्रत्याशियों की कड़ी टक्कर से जीत-हार के समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र में विपक्षी दल से कई गुना ज्यादा वादे किए हैं। वैसे सब्जबाग दिखाने में कोई दल पीछे नहीं है। और अब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ हरियाणा में होड़ लगा रहे हैं। मतदाता मूल्यांकन कर रहा है कि उसे डबल इंजन सरकार चाहिए अथवा परिवर्तन चाहिए। पांच अक्टूबर को ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

संदेह के घेरे में परीक्षा

झारखंड में हुए 21 सितम्बर को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में परीक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। मेरा परीक्षा केंद्र गिरीडीह के श्री गुरु नानक विद्यालय में था, जिसमें हम सभी परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट का सिरियल नंबर अलग-अलग था, जबकि यह दोनों में एक जैसा होना चाहिए। जब हम सभी परीक्षार्थियों ने केंद्राधीक्षक और वीक्षकों को इसकी जानकारी दी तो उन लोगों ने कुछ भी कहने से इनकार किया और कहा कि आपलोग शांतिपूर्वक परीक्षा दें। मजबूरन हमें चुप रहना पड़ा। इस प्रकार की लापरवाही जेएसएससी पर सवाल खड़े करती है। हम सभी परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सरकार इसका जल्द संज्ञान ले।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया करारी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 706-708, सहारा हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
: समूह संपादक - डॉ. विजय राय। सहयोग संपादक - रत्नेश सिन्हा*
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23362371, 23362372, फैक्स - 23362370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 41
आर.एन.आई. नं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कलापूर्ण सामग्री के लिए उत्तरदायी